गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 196
दि. 17.11.2025,
सोमवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

कर्नाटक कांग्रेस में फिर घमासान: कैबिनेट फेरबदल पक्का, नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें तेज

(जीएनएस)। बेंगलुरु। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार एक बार फिर आंतरिक शक्ति-संतुलन के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के बीच चल रहे खींचतान भरे समीकरण, कैबिनेट फेरबदल को लेकर बढ़ती चर्चाएं और नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं पर उठते सवालों ने राज्य की राजनीति का तापमान और बढ़ा दिया है। इन सबके बीच सिद्धारमैया की दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात ने सियासी हलचल को चरम पर पहुंचा दिया है। हालाँकि गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने स्पष्ट कहा कि "नेतृत्व परिवर्तन की बात बेबुनियाद है, सिर्फ कैबिनेट फेरबदल होगा", लेकिन दिल्ली के भीतर चल रही हलचल कुछ और ही संकेत दे रही है।

किन पदों पर हो सकती है नियुक्तियां?

दावा किया जा रहा है कि बड़े स्तर के फेरबदल की बजाय चार प्रमुख पदों पर विचार किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं—

- बी. नागेंद्र और राजन्ना के इस्तीफ़ों के बाद खाली हुए दो मंत्री पद
- विधान परिषद के सभापति और उपसभापति का चुनाव चूंकि कांग्रेस के पास विधान परिषद में बहुमत है, इसलिए पार्टी चाहती है कि सभापति पद पर उसका उम्मीदवार निर्विरोध पहुंचे। साथ ही कुछ मंत्रियों को संगठन की जिम्मेदारी देकर नए चेहरों को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है।

दिल्ली में सिद्धारमैया–राहुल मुलाकात ने बढ़ाया रोमांच

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रविवार को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी से लंबी मुलाकात की। बाहर आकर उन्होंने कहा कि "सिर्फ बिहार चुनाव नतीजों पर चर्चा हुई", लेकिन पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का दावा है कि मुलाकात का मुख्य मुद्दा कर्नाटक का मंत्रिमंडल फेरबदल ही था। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट के कई पुराने चेहरों को संगठन में भेजने और उनकी जगह नए नेताओं को शामिल करने की योजना पर भी चर्चा हुई है। राज्य में कई मंत्री गैर-प्रभावी माने जाते हैं और उनके खिलाफ अंदरूनी नाराजगी भी बढ़ रही है।

डीके शिवकुमार ने अचानक दौरा रद्द कर दिल्ली में बढ़ाई हलचल

उधर, उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अचानक अपना हैदराबाद दौरा रद्द कर दिया और दिल्ली में ही रुकने का फैसला किया। उनके भाई और पूर्व सांसद डी.के. सुरेश भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। यह संकेत साफ है कि शिवकुमार भी अपने राजनीतिक अस्तित्व और शक्ति संतुलन को देखते हुए अपनी भूमिका और दावे मजबूत करना चाहते हैं। शिवकुमार की राहुल गांधी से मुलाकात की कोशिशों ने यह साफ कर दिया है कि वे मंत्रिमंडल के किसी भी विस्तार के खिलाफ हैं। इसके विपरीत सिद्धारमैया चाहते हैं कि जिन मंत्रियों के खिलाफ जनता और संगठन में असंतोष है, उन्हें हटाकर नए लोगों को मौका दिया जाए।

18 नवंबर से तेज होगी हलचल

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सोमवार को दोबारा दिल्ली जाएंगे। इस बार उनका कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 18 नवंबर को एआईसीसी संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल दिल्ली पहुंचेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वेणुगोपाल, सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच तीन-स्तरीय बैठक में अंतिम सहमति बनेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मिलकर फेरबदल पर मुहर लगवाएंगे। कांग्रेस में मंत्री पद की खींचतान नई नहीं है। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी कहा है, "कौन मंत्री बनेगा और कौन जाएगा, यह निर्णय सिर्फ मुख्यमंत्री और आलाकमान का है।"

पाकिस्तान में फिर मंहगाई का विस्फोट, डीज़ल 284 रुपये लीटर पहुंचा; जनता पर बढ़ा बोझ

(जीएनएस)। इस्लामाबाद। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई एक बार फिर चरम पर पहुंच गई है। सरकार ने रविवार देर रात हाई-स्पीड डीज़ल की कीमत छह रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 284.44 रुपये कर दी, जिसके साथ ही परिवहन और कृषि क्षेत्र पर भारी दबाव बढ़ गया है। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं और फिलहाल 15 दिनों तक प्रभावी रहेंगी। पेट्रोल की कीमत में इस बार कोई बदलाव न करने के बावजूद बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि डीज़ल की बढ़ी कीमतें आम जनता की जेब को और अधिक चोट पहुंचाएँगी। सूत्रों के अनुसार, ओजीआरए और संबंधित मंत्रालयों के साथ कई दौर की समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, जिनके बाद यह निर्णय लिया गया। डीज़ल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले परिवहन क्षेत्र का प्रमुख ईंधन है। ट्रकों से लेकर बसों और ट्रेनों तक अधिकांश भार वाहनों की रोज़मर्रा की परिचालन लागत सीधे इसी ईंधन से जुड़ी होती है। यही वजह है कि डीज़ल महंगा होते ही देश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें ऊपर चढ़ने लगती हैं। सब्जियों,

अनाज और दालों से लेकर रोज़मर्रा के उपयोग की वस्तुओं तक सबकी ढुलाई लागत बढ़ने की आशंका है, जिसका सीधा असर खुदरा उपभोक्ता पर पड़ेगा।

विशेषज्ञ बताते हैं कि पाकिस्तान में मध्यम और निम्न वर्ग पहले से ही महंगाई के दबाव में है। पेट्रोल भले ही स्थिर रखा गया है, मगर डीज़ल में वृद्धि हर उस वर्ग को प्रभावित करेगी जो परिवहन सेवाओं पर निर्भर है। ट्रैक्टर, थ्रेसर, ट्यूबवेल और अधिकांश कृषि उपकरण डीज़ल से चलते हैं, इसलिए किसानों की लागत भी बढ़ेगी, जिसका असर आने वाले महीनों में कृषि उत्पादों की कीमतों पर साफ दिखाई दे सकता है। देश में पहले ही खाद्य सामग्रियों की लागत लगातार बढ़ रही है और अब डीज़ल महंगा होने से यह दबाव और बढ़ेगा।

दिलचस्प बात यह है कि सरकार हर लीटर पर लगभग 99 रुपये टैक्स के रूप में वसूल कर रही है। भले ही जीएसटी को शून्य कर दिया गया है, लेकिन पेट्रोलियम लेवी, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी, सीमा शुल्क और वितरण मार्जिन मिलाकर कुल मिलाकर ईंधन की कीमत का बड़ा हिस्सा सीधे सरकारी राजस्व में जाता है। रिपोर्टों के अनुसार डीज़ल पर 79.50 रुपये, जबकि पेट्रोल और हाई-ऑक्टेन उत्पादों पर 80.52 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगाया जा रहा है। करीब 17–18 रुपये सीमा शुल्क और 17 रुपये वितरण व बिक्री मार्जिन जोड़ने के बाद ईंधन उपभोक्ता तक काफी महंगा पहुंचता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीज़ल की संयुक्त खपत हर महीने 7 से 8 लाख टन के बीच रहती है, जबकि केरोसिन की मांग महज 10 हजार टन के आसपास है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान पेट्रोलियम लेवी से होने वाला संग्रह 1.161 ट्रिलियन रुपये तक पहुँच चुका है और मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए इसमें कम से कम 27 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञ इसे सरकार के लिए राजस्व जुटाने का आसान स्रोत बताते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी देते हैं कि इससे महंगाई और बढ़ेगी, जिससे आम जनता का जीवन और कठिन हो जाएगा।

देश में पहले से मौजूद आर्थिक संकट, अंतरराष्ट्रीय कर्ज़ शर्तों, मुद्रा अवमूल्यन और राजनीतिक अस्थिरता के बीच यह नई मूल्य बढ़ोतरी जनता के लिए एक और झटका मानी जा रही है। बाज़ारों में पहले ही खाने-पीने की वस्तुएँ महंगी हैं और अब परिवहन व कृषि क्षेत्र पर बढ़े बोझ से आने वाले हफ्तों में महंगाई का नया दौर देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान की आम जनता जो पहले से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है, अब डीज़ल की बढ़ी कीमतों के साथ एक और चुनौती का सामना कर रही है।

प्रियंक खड़गे का RSS पर तीखा प्रहार: "100 साल में पहली बार कानून मान रहा संघ"

(जीएनएस)। नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे ने रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को निशाने पर लेते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। खड़गे ने कहा कि चित्तापुर में आयोजित होने वाले RSS कार्यक्रम के लिए संगठन द्वारा प्रशासन से औपचारिक अनुमति मांगना इस बात का संकेत है कि "संघ अपनी 100 साल की यात्रा में पहली बार कानून का पालन करता हुआ दिखाई दे रहा है।" कांग्रेस नेता ने कहा कि यह वही संगठन है जो वर्षों से सरकारी अनुमतियों को 'औपचारिकता' मानकर चलता रहा, लेकिन अब प्रशासनिक सख़्ती के चलते नियमों को स्वीकार करने पर मजबूर है।

खड़गे के अनुसार चित्तापुर प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए कड़े नियम तय किए हैं, जिन्हें RSS प्रतिनिधियों को लिखित रूप में दिया गया है। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करना स्वागतयोग्य है, परंतु यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्ती से होगी। मंत्री ने आरोप लगाया कि इससे पहले RSS 'पथ संचलन' और इसी तरह के आयोजनों के लिए अनुमति न लेने की परंपरा का हवाला देता रहा, और कई बार नियमों को नजरअंदाज करता रहा। उन्होंने कहा कि इस बार स्थिति अलग इसलिए है क्योंकि प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि एक संगठन का कानून के प्रति झुकना प्रशासनिक दृढ़ता का प्रमाण है।

इस दौरान प्रियंक खड़गे ने बिहार चुनाव के नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व विस्तृत समीक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया, संस्थागत भूमिका और स्थानीय घटनाक्रमों से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। खड़गे ने दावा किया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में प्राप्त आंकड़े किसी न किसी अनियमितता की ओर इशारा कर रहे हैं और "डेटा चाहे एक-दो दिन रोका जाए, लेकिन अंततः सच्चाई खुद सामने आ जाती है।" उन्होंने कहा कि अलंद, महादेवपुर, हरियाणा और महाराष्ट्र से जुड़े कई मामलों में पार्टी के पास पर्याप्त दस्तावेज़ और प्रमाण मौजूद हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि कई जगहों पर प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी।

केंद्र की राजनीति में चल रही संभावित कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं पर मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सब मीडिया की कल्पना है और वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट के भीतर इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है और यह खबरें केवल बाहर फैलाई जा रही हैं। प्रियंक खड़गे के बयान ने एक ओर जहां RSS–कांग्रेस राजनीतिक संघर्ष को नई परत दी है, वहीं यह भी साफ किया है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक की राजनीति और अधिक तेज़ बहसों का केंद्र बनने वाली है।

मौलाना रजवी का बड़ा बयान: 'भाजपा को रोकना सिर्फ मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं', धर्मनिरपेक्ष दलों से भी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद देशभर में राजनीतिक बहस तेज है, इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने एक महत्वपूर्ण और तीखा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भाजपा को रोकने का जिम्मा केवल मुसलमानों पर डालना न तो सही है और न ही व्यावहारिक। उनके अनुसार, जो पार्टियां खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, उन्हें भी उतनी ही सक्रियता और जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

मौलाना रजवी ने कहा कि बिहार के नतीजों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति का दावा करने वाले दल आख़िर अपने वोटरों और रणनीतियों के प्रति कितने सजग और प्रभावी हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को बार-बार यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि सिर्फ वही भाजपा के खिलाफ लड़ें। उन्होंने टिप्पणी की,

"भारत में ऐसा माहौल बन गया है कि भाजपा को रोकने की ज़िम्मेदारी जैसे सिर्फ मुसलमानों ने ले ली है। यह जिम्मेदारी अकेले मुसलमानों की नहीं, बल्कि उन सभी पार्टियों की है जो खुद को धर्मनिरपेक्ष बताती हैं। बिहार चुनाव के परिणाम मुसलमानों के लिए सोचने और अपना नजरिया बदलने का अवसर हैं।"

ओवैसी की सीमांचल में सफलता को बताया प्रभावशाली मौलाना रजवी ने सीमांचल क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM के प्रदर्शन की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ओवैसी पिछले कुछ समय से सीमांचल में लगातार सक्रिय हैं और इस चुनाव में उनकी मेहनत दिखी है।

लाल किला ब्लास्ट की गुत्थी सुलझने की ओर: i20 कार मालिक गिरफ्तार, डॉक्टर उमर निकला आत्मघाती हमलावर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के लाल किला क्षेत्र में 10 नवंबर को हुए कार बम धमाके की जांच में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने उस i20 कार के मालिक आमिर राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके नाम पर धमाके में इस्तेमाल की गई कार रजिस्टर्ड थी। एजेंसी के अनुसार आमिर ने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी के साथ मिलकर इस पूरी आतंकी साजिश को अंजाम देने में निर्णायक भूमिका निभाई।

आमिर को 11 नवंबर को पकड़ा गया था और कई दिनों की पूछताछ, उसके फोन, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल सबूतों की बारीकी से जांच करने के बाद रविवार को आधिकारिक रूप से गिरफ्तार किया गया। वह जम्मू-कश्मीर के सांबूरा, पंपोर का रहने वाला है और उस पर आरोप है कि उसने कार खरीदकर उसे इस हमले में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि आतंकी मॉड्यूल में उसकी भागीदारी केवल वाहन खरीदने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह इसमें गहरे स्तर पर शामिल था।

धमाके में शामिल आत्मघाती हमलावर की पहचान ने जांच को और चौंकाने वाली दिशा दी है। फोरेंसिक जांच से पुष्टि हुई कि कार चलाने वाला युवक उमर उन नबी था, जो पेशे से डॉक्टर था और हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जनरल मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत था। पुलवामा निवासी उमर का इस तरह आतंकी गतिविधि में शामिल होना सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक बड़ा सवाल बनकर उभरा है कि आखिर एक शिक्षित डॉक्टर कैसे ऐसे मॉड्यूल का हिस्सा बन गया।

जांच में एक और महत्वपूर्ण प्रगति तब हुई जब एनआईए ने उमर की एक दूसरी कार भी जब्त कर ली। दोनों वाहनों के GPS डेटा, तकनीकी विश्लेषण और विस्फोटक तत्वों के अवशेषों की जांच जारी है। इस दौरान एनआईए अब तक 73 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें धमाके में घायल लोग भी शामिल हैं। दिलचस्प बात यह रही कि सरकारी प्रेस रिलीज में मृतकों की संख्या 10 बताई गई, जबकि शुरुआती पुलिस बयान में इसे 13 बताया गया था। यह विस्फोट लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ था, जिसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी थी।

जांच केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रही। दिल्ली पुलिस के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सहित कई राज्यों की पुलिस एजेंसियाँ एनआईए के साथ मिलकर पूरे मॉड्यूल की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई हैं। केस नंबर RC-21/2025/NIA/DLI के तहत चल रही जांच अब एक बहु-राज्य ऑपरेशन में बदल चुकी है। जम्मू-कश्मीर में 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, हालांकि ज्यादातर को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। अब तक केवल चार आरोपियों—डॉ. अदील, डॉ. मुझम्मिल, डॉ. शाहीन और मौलवी इरफान—के खिलाफ ही पुख़्ता सबूत मिले हैं। बाकी सभी संदिग्धों को केवल पूछताछ के आधार पर रोका गया है।

रविवार को दिल्ली में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। लाल किला मेट्रो स्टेशन को फिर से खोल दिया गया और स्टेशन के बाहर लगाया गया सफेद परदा हटा दिया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में लगातार छापेमारी चलती रही और उमर के दो और करीबी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। सबसे ज्यादा चिंता उन कारतूसों ने बढ़ाई, जो धमाके वाली जगह से मिले—तीन 9mm के कारतूस, जिनमें दो जिंदा और एक खाली खोखा था। यह कारतूस नागरिकों के लिए प्रतिबंधित श्रेणी में आते हैं। इससे सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या किसी आधुनिक हथियार का इस्तेमाल हुआ, जो अभी तक बरामद नहीं हुआ है, या फिर यह मॉड्यूल हथियारों की सप्लाई के किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

एनआईए फिलहाल सभी कोणों—डिजिटल सबूतों, बम अवशेषों, हथियारों की संभावित आपूर्ति, विदेश लिंक, और आतंकी संगठनों के साथ मॉड्यूल के संबंध—पर गहराई से काम कर रही है। एजेंसी का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाज़ी होगी। लेकिन आमिर की गिरफ्तारी और उमर की पहचान ने इस मामले को एक निर्णायक मोड़ दे दिया है, जिससे यह साफ हो रहा है कि यह हमला बेहद संगठित, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और संभावित रूप से अंतरराष्ट्रीय मॉड्यूल का हिस्सा था। दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा।

संपादकीय

सबक सिखाने वाला हादसा, फरीदाबाद से विस्फोटक श्रीनगर ले जाने पर भी सवाल

इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं कि जो जम्मू-कश्मीर पुलिस अपनी अतिरिक्त सतर्कता के चलते फरीदाबाद के खतरनाक आतंकी माड्यूल तक पहुंची, वह उसी विस्फोटक के एक हिस्से में हुए विस्फोट की चपेट में आ गई, जिसे उसने बरामद किया था। श्रीनगर के नौगाम थाने में हुए विस्फोट में नौ लोगों ने जान गंवाई।

विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट नामक उस विस्फोटक में हुआ, जिसका इस्तेमाल फरीदाबाद माड्यूल के एक आतंकी की कार में दिल्ली में लाल किले के निकट हुआ था। उसकी कार में हुए धमाके से 13 लोग मारे गए थे। यदि फरीदाबाद में विस्फोटक मिलते ही उसका भंडारण करने वाले आतंकियों के शेष साथियों की गहन तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती तो शायद लाल किले के निकट हुए धमाके को रोका जा सकता था।

इसी तरह यदि फरीदाबाद में मिले विस्फोटक को श्रीनगर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती तो नौगाम थाने के जानलेवा हादसे से बचा जा सकता था। ये दोनों प्रसंग यही सबक दे रहे हैं कि पुलिस को और अधिक सजगता बरतने और अपनी कार्यप्रणाली में परिवर्तन लाने की जरूरत है।

फरीदाबाद में आतंकियों के ठिकाने से बरामद विस्फोटक को श्रीनगर के नौगाम थाने इसलिए ले जाया गया, क्योंकि इस आतंकी माड्यूल के खिलाफ एफआइआर यहीं दर्ज की गई थी। आखिर विस्फोटक के एक अंश को नमूने के तौर पर ले जाने के बजाय उसकी इतनी अधिक मात्रा क्यों ले जाई गई? अच्छा हो कि संवेदनशील विस्फोटकों को संबंधित थाने ले जाने की बाध्यता खत्म की जाए।

अमोनियम नाइट्रेट बहुत ही संवेदनशील और अस्थिर प्रकृति का विस्फोटक है। तनिक भी असावधानी या प्रतिकूल परिस्थिति उसमें विस्फोट का कारण बन सकती है। यह ठीक नहीं कि खतरनाक विस्फोटक को बड़ी मात्रा में फरीदाबाद से श्रीनगर ले जाया गया और जब उसका परीक्षण किया जा रहा था तो तमाम सावधानी के बाद भी उसमें विस्फोट हो गया।

आज जब आतंकियों का नेटवर्क देशव्यापी होने लगा है और वे घातक विस्फोटक कई ठिकानों में छिपाने लगे हैं, तब उन्हें हर जगह से उसी थाने ले जाना जरूरी नहीं होना चाहिए, जहां से मामले की जांच शुरू हुई हो। आतंकियों के पास से मिले विस्फोटकों के मामले में तो इस चलन को रोका ही जाना चाहिए। अब हर राज्य में आतंकवाद निरोधक दस्ता है। उसे यह सुविधा मिले कि अन्य राज्यों की पुलिस के लिए विस्फोटकों की जांच कर सके।

आखिर फरीदाबाद में मिले विस्फोटक की जांच हरियाणा में ही क्यों नहीं हो सकती थी? प्रश्न यह भी है कि जब फरीदाबाद माड्यूल का भंडाफोड़ होते ही यह स्पष्ट हो गया था कि यह आतंकवाद से जुड़ा मामला है और इसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी अपने हाथ में लेगी, तब भी विस्फोटक श्रीनगर क्यों ले जाया गया?

डीपफेक से निपटने को फौरी समाधान से आगे बढ़ें

> भारत को न केवल डीपफेक से, बल्कि एआई के सभी पहलुओं से निपटने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचे की आवश्यकता है, जैसा कि यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम में है। न कि विनियमन के लिए टुकड़ों-टुकड़ोंवाली अथवा पैबंद लगाने वाले दृष्टिकोण की।

केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से उत्पन्न डिजिटल सामग्री के नियमन के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। वर्ष 2021 में जारी हुए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियमों को विस्तार करते हुए, इस मसौदे में 'कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी' को भी शामिल किया गया है। ऐसी जानकारी या सामग्री को ऐसी चीज़ के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके कृत्रिम रूप से या एल्गोरिथम के माध्यम से निर्मित, उत्पन्न, संशोधित अथवा परिवर्तित कुछ इस तरह से किया गया हो कि वह यथोचित रूप से प्रामाणिक या सत्य प्रतीत लगे। ये नियम विशेष रूप से डीपफेक वीडियो, ऑडियो और सिंथेटिक मीडिया के खतरे से निपटने के लिए तैयार किए गए हैं, जिनकी हाल के महीनों में सोशल प्लेटफॉर्म पर बाढ़ आई हुई है। ये 'विश्वसनीय' लगने वाले झूठ फैलाने के लिए जनरेटिव एआई की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। ऐसी सामग्री में व्यक्तियों को ऐसे कार्य करते अथवा बयान देते दर्शाया जाता है, जो उन्होंने कभी किया ही नहीं।

एआई-जनित डीपफेक का इस्तेमाल अक्सर गलत सूचना फैलाने, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने या वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है। राजनीतिक दल चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकारी एजेंसियों की अब तक की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों' (एसएसएमआई) को 'आपत्तिजनक' सामग्री के खिलाफ परामर्श नोट जारी करना ही रही है। एसएसएमआई के पास शिकायतों और नियामक आवश्यकताओं

से निपटने के लिए एक अनुपालन प्रणाली होने की जरूरत थी। नए नियमों का उद्देश्य कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचना से संबंधित लेबलिंग, मूल स्रोत का पता लगाने की क्षमता और जवाबदेही के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करना है। ऐसा तमाम एआई-जनित सामग्री को मेटाडेटा एम्बेडिंग के माध्यम से लेबल करने के लिए बाध्यकारी बनाया जाएगा ताकि कृत्रिम रूप से उत्पन्न या संशोधित जानकारी की शिनाख्त प्रामाणिक सामग्री से अलग की जा सके। सोशल मीडिया मध्यस्थ कृत्रिम जानकारी की पुष्टि और उसे चिह्नित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इस प्रकार प्रस्तावित उपायों में न केवल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और मध्यस्थ को शामिल किया है, बल्कि कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी के निर्माण या संशोधन हेतु तकनीक प्रदान करने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंपनियां और उपकरण भी शामिल हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल्स कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसी जानकारी में स्थायी, विशिष्ट मेटाडेटा, पहचानकर्ता के साथ, लेबल या एम्बेड किया हो। तंबाकू उत्पादों पर छपी वैधानिक स्वास्थ्य चेतावनी की तरह, कृत्रिम सामग्री पर लेबल को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, जो विज़ुअल डिस्प्ले के कम से कम 10 प्रतिशत सतह क्षेत्र में दिखाई दे अथवा ऑडियो सामग्री के मामले में प्रारंभिक 10 फीसदी अवधि में सुनाई देता हो। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के लिए जरूरी है उपयोगकर्ताओं से यह घोषणा करने के लिए कहें कि जो जानकारी वे अपलोड कर रहे हैं कहीं वह कृत्रिम रूप से उत्पन्न तो नहीं, और प्लेटफ़ॉर्मों को ऐसी घोषणाओं को सत्यापित करने के लिए 'उचित एवं आनुपातिक' तकनीकी उपाय करने होंगे। यदि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अच्छी भावना से कृत्रिम बुद्धिमत्ता-जनित या अन्य समस्याग्रस्त सामग्री को खुद से हटा देते हैं या उस तक पहुंच को अवरुद्ध करते हैं, तब वे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत प्रदत्त कानूनी सुरक्षा नहीं खोएंगे। इस तकनीक की प्रकृति और संरचना के कारण, किसी भी प्रकार के एआई को विनियमित करना दुनिया भर के नियामकों और सरकारों के लिए एक दुःस्वप्न साबित हो रहा है। एआई सामग्री श्रृंखला जटिल और बहुस्तरीय है। यह केवल चैटजीपीटी, जेमिनी या डैल-ई जैसे एआई टूल्स ही नहीं हैं, बल्कि कई मध्यस्थ और प्लेटफ़ॉर्म भी हैं, जो एआई-जनित सामग्री जैसे कि एआई आर्ट जनरेटर, वॉइस-क्लोनिंग टूल्स, डीपफेक ऐप्स, सोशल मीडिया या वीडियो प्लेटफ़ॉर्म में एम्बेडेड टूल है, जिन पर उपयोगकर्ता एआई-जनित सामग्री, चैटबॉट या सामग्री निर्माण टूल्स अपलोड करते हैं, जो आगे एआई टेक्स्ट या विज़ुअल उत्पन्न करते हैं। इनके निर्माण या साझाकरण को सक्षम, अनुमति या सुगम बनाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और लिंक्डइन जैसे प्रमुख सोशल मीडिया प्लेयर्स, जिनकी भारत में उपस्थिति है, इनको छोड़कर, एआई श्रृंखला के अधिकांश प्लेयर्स कहीं और स्थित हैं। उन्हें भारतीय नियमों के अधीन लाना कठिन हो सकता है। डीपफेक से संबंधित नियम जल्दबाजी में बनाए गए प्रतीत होते हैं। ये नागरिकों के ऑनलाइन अधिकारों की रक्षा के लिए एक सुविचारित नियामक कदम के बजाय, हाल ही में राजनीतिक नेताओं से जुड़े डीपफेक वीडियो की बाढ़ के प्रति एक अतिशयी प्रतिक्रिया अधिक प्रतीत होते हैं। नियमों के ध्यान का केंद्र मुख्यतः आपत्तिजनक माने जाने वाले डीपफेक को 'हटाना' और ऐसी सामग्री के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार ठहराना है। इसकी बजाय, नियमन को हर किसी की शारीरिक संरचना और आवाज़ के अधिकार की रक्षा के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। भारत में फ़िल्मी सितारे ख़ास तौर पर अपने चेहरे और आवाज़ के अनधिकृत एआई उपयोग को रोकने के लिए इस अधिकार की मांग कर रहे हैं।

इस दिशा में डेनमार्क ने सिर्फ़ मशहूर हस्तियों की ही नहीं, किसी भी व्यक्ति की अनूठी पहचान को, बल्कि सभी नागरिकों की, बौद्धिक संपदा की तरह मानने का प्रस्ताव रखा है। अमेरिका में एक प्रस्तावित क़ानून संघीय चुनावों में उम्मीदवारों के बारे में एआई द्वारा उत्पन्न भ्रामक ऑडियो या विज़ुअल सामग्री के जानबूझकर वितरण पर रोक लगाता है। फ़्रांस एक व्यापक ऑनलाइन सुरक्षा क़ानून पर काम कर रहा है। ब्रिटेन ने डीपफेक और अंतरंग छवि दुरुपयोग को शामिल करने के लिए अपने ऑनलाइन सुरक्षा क़ानून में संशोधन किया है। सबसे बृहद क़ानून यूरोपीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम है।

भारत में मसौदा नियमन का बिना किसी सार्वजनिक बहस के प्रस्तावित किया गया है। विनियमन के इतने महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक, बहु-हितधारक चर्चा करवाना जरूरी है। विमर्श में 2021 से लागू डिजिटल मीडिया आचार संहिता की प्रभावशीलता को भी शामिल किया जाना चाहिए। सरकारी एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग और सामग्री को चुनिंदा रूप से हटाए जाने का डर हमेशा बना रहेगा। वरिष्ठ सरकारी और राजनेता जानबूझकर या अनजाने में नकली और एआई-जनित सामग्री का उपयोग करते पाए गए हैं। सबसे बड़ी समस्या गुमनाम और बॉट-संचालित खातों पर तकनीकी कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का संदिग्ध रुख है।

भारत को न केवल डीपफेक से, बल्कि एआई के सभी पहलुओं से निपटने के लिए एक व्यापक नियामक ढांचे की आवश्यकता है, जैसा कि यूरोपीय संघ के एआई अधिनियम में है। न कि विनियमन के लिए टुकड़ों-टुकड़ों वाली अथवा पैबंद लगाने वाले दृष्टिकोण की। इसका डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने और ऑनलाइन सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के बारे में शिक्षा के संग-संग चलना जरूरी है।

प्रेरणा

ममता की वह आख़िरी रोशनी, जिसे कोई देख न सका

मालती जी के जीवन में जैसे किसी ने धीरे-धीरे रोशनी कम कर दी हो। कभी यह घर हँसी से भरा रहता था, दीवारों तक में बेटे की खनकती आवाज़ गूँजती थी, और रसोई से उठते हुए मसालों की खुशबू में माँ-बेटे का जादुई रिश्ता घुला रहता था। पर वक्त की रफ्तार ऐसी थी कि मालती को समझ ही नहीं आया, कब दीपक बड़ा हो गया, कब अपनी दुनिया बसाने के नाम पर उनसे दूर चला गया, और कब उनका अपना मकान किसी सूने बरामदे की तरह सिर्फ धूप और परछाइयों में बदल गया।

नई पीढ़ी का "जियो और जीने दो" जैसा चमकदार दर्शन बाहर से जितना दमकता दिखता है, अंदर से उतना खोखला है। दीपक ने भी उसी विचार को अपनाया—"अपनी जिंदगी अलग, अपने फैसले अलग।" मालती को यह आधुनिकता पहले तो बड़ी प्यारी लगी। उन्होंने खुद को समझाया कि बेटे की आज़ादी में ही उसकी भलाई है। पर भलाई की इन दलीलों के पीछे एक बूढ़ी माँ की काँपती अकेलापन छिपा होता है, जिसे आधुनिक शब्दों से छुपाया तो जा सकता है, भरा नहीं जा सकता। दीपक जब नए घर में चला गया, तब मालती ने खुद को समझाया—"अब मैं अति-आधुनिक माँ हूँ।"

पर अति-आधुनिक माँ होना, असल में अपने ही दिल को रोज़ थोड़ा-थोड़ा काटकर मुस्कुराने का नाम है। दीपक त्योहारों पर आता तो था, पर जैसे किसी औपचारिकता की तरह। वह दरवाज़े पर मुस्कुराता, 'कैसी हो माँ?' कहता और चाय का कप हाथ में लेकर सोफ़े पर बैठ जाता। मालती उतने में रसोई में जाकर अपने आँसू पोंछ लेतीं, क्योंकि अब वह मातृत्व का रुतबा नहीं था, जिसे देखकर बेटा पूछ ले कि "माँ, क्या हुआ?" और माँ वह सब बता दे जो दिल पर जमा बर्फ़ की तरह बैठा था। अब वह बस एक 'मौन देखभाल' थी, जिसे बेटे को बताना अनुचित समझा जाता था, और बेटे को महसूस करना गैरज़रूरी।

किसी वक्त माँ की राय घर की धुरी हुआ करती थी, पर नए ज़माने में माँ की राय सिर्फ एक 'पुरानी आदत' मानी जाती है, जिसे सुना जाना शिष्टाचार है, माना जाना ज़रूरी नहीं। दीपक भी यही समझता था। उसे माँ का स्नेह चाहिए था, राय नहीं। मालती ने यह धीरे-धीरे सीख लिया कि अब वह सिर्फ त्योहार की मिठाई और घर के कोने में रखा एक पुराना भावुकपन हैं।

लेकिन फिर एक दिन दीपक आया। उसी सहज मुस्कान के साथ, पर उसकी आँखों में थोड़ा-सा हिचकिचाहट भी। और उसने कहा—"माँ आज आपसे एक राय चाहिए।"

यह शब्द जैसे मालती के भीतर किसी बंद कुएँ में अचानक पानी की बूंद गिर गई हो। वर्षों से अछूती पड़ी ममता जैसे अचानक जाग उठी। उनके होंठ थरथराए, आँखों में चमक दौड़ गई। उन्हें लगा, मेरा बेटा फिर वही बच्चा बनकर आया है, जो हर बात पूछता था। उन्हें लगा, आज उनकी ज़िंदगी फिर से मूल्यवान हो गई। वे हड़बड़ा गईं, उलझ गईं, जैसे वर्षों बाद किसी ने उनका नाम पुकारा हो। पर दीपक राय लेने नहीं आया था। वह अपनी सुविधा के लिए आया था। उसने सोने की बाली की कहानी सुनाई—चार महीने पहले सड़क पर मिली, फिर सोचा किसी की होगी, इसलिए मंदिर में रख दी। फिर मन का बोझ बढ़ा तो बेच दी, और अब मन में पाप-बोध है। 2400 रुपये आए, पर उन्हें घर लाने से डर रहा है। पत्नी को नहीं बताया, क्योंकि पत्नी उन पैसों से कुछ खरीद लेती, और वह सोचता रहा कि इस पैसे में किसी अनजानी औरत का दुख जुड़ा है। और इसलिए वह माँ के पास आया—इस उम्मीद में कि माँ अपनी ममता से उसके इस 'पाप' को धो देगी।

मालती सुनती रहीं। उनके मन में टीस उठी—चार महीने पहले बेटे ने सोना पाया, बेच दिया, पैसा रख लिया—पर यह बात माँ को आज बताई जा रही है, जब उसका मन डर और अपराध से भर गया है। उसकी खुशी या उसके जीवन का कोई बड़ा फैसला माँ की जानकारी में नहीं आता, पर उसके अपराध की सफाई माँ को देनी ज़रूरी समझी जाती है। जैसे माँ से सिर्फ पाप धुलवाए जाते हैं, दुख नहीं बाँटे जाते।

मालती ने कहा—"बेटा, जिस धन में किसी का दुःख जुड़ा हो, उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए।" यह सिर्फ सोना बेचने वाले बेटे को सलाह नहीं थी—यह उनकी अपनी पीड़ा थी। वह कहना चाह रही थीं—"बेटा, मेरे जीवन में भी मेरा दुख जुड़ा है मेरा क्या करूँ मैं? कौन रखेगा मेरे दुःख को?"

उन्होंने आगे कहा—"अगर तुम्हें लगता है कि यह पैसे तुम्हें बोझ लगते हैं, तो इन्हें किसी जरूरतमंद को दे दो या कन्याओं को। उनका आशीर्वाद बड़ा शुभ होता है।"

यह दान नहीं था, यह बेटे की मन की अपराधी भावना को शांत करने का रास्ता था—नैतिक धुलाई। जिन पैसों को खर्चने से डर लग रहा था, जिन्हें अपने पास रखने में एक काँटा चुभ रहा था—उन्हें गरीबों पर डालकर हल्का महसूस कर लेना। समाज की गरीब जनता मानो एक ऐसा टोकरा है, जहाँ अमीर अपने दोष डालकर खुद को पवित्र साबित करते हैं। और कन्या पूजन—2400 का पाप बच्चियों की हँसी में धुल जाएगा। यही तो तरीका है—अपराध से पुण्य की ओर, और इस सफर में सबसे ज़रूरी है किसी माँ की स्वीकृति।

दीपक ने सिर हिलाया—"अब समझ आया माँ, शुभता वस्तु में नहीं, भावना में होती है।"

मालती के दिल ने अलमारी खोलकर इस वाक्य को रखने से मना किया—क्योंकि यह झूठ था। भावना होती तो सोना मिलते ही सही काम करता। भावना होती तो माँ का दर्द भी समझता। पर वह बेटे की इस आधी-अधूरी समझ को भी अपने सीने से लगा लेती हैं, क्योंकि माँ को अपने बेटे की नादानियाँ भी प्रसाद जैसी लगती हैं।

बिहार में नीतीश कुमार का जादू बरकरार

बिहार में मुकाबला मुख्य रूप से जदयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए और राजद के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन के बीच था। इस बार प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव-2025 के एक्जिट पोल नतीजे के बाद जो आश्चर्यकारी परिणाम आये हैं, उसकी गूंज आने वाले पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट रूप से दिखायी देगी। लोकतंत्र के इस मंदिर की चैखट पर विराजमान दृश्य कुछ ऐसा है जिसमें हालात किसी एक पार्टी तक ही सीमित नहीं, बल्कि सभी प्रमुख दलों में टिकटों की दावेदारी में राजद व कांग्रेस और जदयु व भाजपा, लोजपा और इसके साथ ही कोई भी अन्य दल इनसे अछूता नहीं है। 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में भेजने के कारण महिला मतदाताओं का प्रतिशत बढ़ा और उन्होंने नीतीश सरकार के लिए जमकर मतदान किया जो आज के चुनाव परिणाम में दिखाई दे रहे हैं, इस चुनाव परिणाम ने सारे एग्जिट पोल को झुठला दिया। इस चुनाव परिणाम ने जदयू, भाजपा एनडीए गठबंधन की सत्ता को बरकरार रखा बल्कि उनकी ताकत एवं सीटों में इजाफा पहले से बहुत ही बेहतर हुआ है। चुनाव परिणाम ने साबित कर दिया कि नीतीश का जादू अभी भी बिहार में बरकार है। बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों ने जनता के बदलते मन-मिजाज की एक झलक पेश की है। ताजा चुनाव परिणाम शायद इसी ओर इशारा कर रही है कि कुल मिलाकर जदयू, बीजेपी एवं एनडीए के लिए एक बड़ी सफलता है। क्या पीएम मोदी बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर कोई बड़ा फैसला करेंगे और इसके साथ ही अब वह क्या रणनीति अपनाएंगे, यह आनेवाले दिनों में पता चलेगा। विधानसभा चुनाव में जनता स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो देती है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत करिश्मे के सहारे चुनाव दर चुनाव जीत रही है और मोदी का वह करिश्मा बिहार में भी आश्चर्यकारी परिणाम लाये हैं क्योंकि बिहार में सुशील मोदी के निधन के बाद उनके स्तर का नेता आज भी नहीं है। ताजा चुनाव नतीजों को नीतीश भाजपा की गठबंधन सरकार के कामकाज पर टिप्पणी की तरह ही देखा जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की दर्जनों रैलियां बताती हैं कि एनडीए इस चुनाव को लेकर कितना संवेदनशील है। क्योंकि इसका असर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी असर देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार का प्रदर्शन पहले से बेहतर हुआ है, खास तौर पर महिलाओं की वजह से, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर उनका नाम औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया गया। इससे उनका वोटर कुछ असहज रहा। राजद महागठबंधन का स्तर बहुत मुश्किल भरा रहा है, आरजेडी अपने पिछले प्रदर्शन को भी कायम नहीं रख सकी 1 नंबर से वह 3 नंबर पर पहुंच गई, इस बार का उसका प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक रहा, उसके मुद्दे और वायदे जनता को पिछली बार की तरह नहीं आकर्षित कर पाई। सत्ता में उसकी आने की कोशिश और पीछे चली गई। पिछली बार आरजेडी ने 75 सीटें जीती थीं, जो आज 28 सीटों पर सिमट कर रह गई। सरकारी नौकरियां, माई बहन योजना, 30000 रुपये महिलाओं को सरकार बनते ही एकमुश्त देने की घोषणा एवं आजीविका दीदी को पक्की नौकरी और उनकी वेतन 30000 रुपये तक करने का वायदा भी कुछ खास असर नहीं कर पाया।

जनसुराज पार्टी की स्थिति मोटे तौर पर निराशाजनक ही कही जाएगी, क्योंकि वह पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाया। प्रशांत किशोर खुद कहते रहे हैं कि या तो अर्श पर होंगे या फर्श पर। अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए वे इसे अपने बयान की पुष्टि ही मानेंगे। प्रशांत किशोर ने शुरुआत में कहा था कि वे राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में पीछे हट गए, इससे उनके कार्यकर्ता निराश हुए, जब नेता ही मैदान छोड़ दे, तो कैडर का मनोबल गिरना स्वाभाविक है। महागठबंधन में भी तालमेल की कमी दिखी। चुनाव से दस दिन पहले तक पार्टियों में बातचीत नहीं हो रही थी। पिछली बार के मुकाबले नीतीश कुमार की सीटें बढ़ी, एनडीए के भाजपा सहित सभी दलों ने अपना स्ट्राइक रेट बेहतर किया है। पहले के चुनाव में चिराग पासवान नीतीश के विरोध में लड़े थे, लेकिन इस बार वह नीतिश के साथ थे, इससे दोनों दलों एवं एनडीए गठबंधन को इसका फायदा मिला। बिहार के लोगों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति भरोसा अभी भी बना हुआ है। चुनाव परिणाम ने पूर्व के सारे अनुमान को गलत साबित कर दिया क्योंकि एंटी-इनकंबेंसी का असर घोषित चुनाव परिणाम में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिहार में कुल 67.13 फीसदी का रिकॉर्ड मतदान हुआ। लेकिन महिलाओं ने इससे भी आगे बढ़कर 71.78 फीसदी मतदान किया, जबकि पुरुषों का मतदान फीसदी 62.98 प्रतिशत रहा। कई जिलों में महिलाओं ने पुरुषों से 10 से 15 फीसदी ज्यादा वोटिंग की। महिलाएं पिछले 15 सालों से लगातार ज्यादा संख्या में वोट कर रही थीं, लेकिन 2025 में उनकी भारी भागीदारी ने सबको चैंका दिया।

नीतीश कुमार की 10वीं पारी सुनिश्चित करने में महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये का कैश ट्रांसफर टर्न अराउंड का सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ। महिला वोटरों का भरोसा उनके पक्ष में मजबूत हुआ और विपक्ष की रणनीति कमजोर पड़ गई। नीतीश की ये स्कीम चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। इस योजना के तहत 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए। इसका अप्रत्यक्ष असर लगभग 4 से 5 करोड़ परिवारों पर पड़ा। कहा जा सकता है कि इस स्कीम ने नीतीश और बीजेपी को तगड़ा वोट हासिल करने में मदद की है। महिलाओं के पक्ष में स्कीम डिलीवरी का नीतीश कुमार का लंबा इतिहास रहा है। इसमें मुफ्त साइकिल, शराबबंदी, छात्रवृति, पंचायत में 50 प्रतिशत सीटों का आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण अहम हैं। इस बार नीतीश कुमार ने 10 हजार नगदी देने का न सिर्फ वादा किया बल्कि इसे डिलीवर भी किया।

अभियान

घर में शिवलिंग की स्थापना बदल सकती है आपकी पूरी किस्मत: बस इन नियमों का रखें विशेष ध्यान

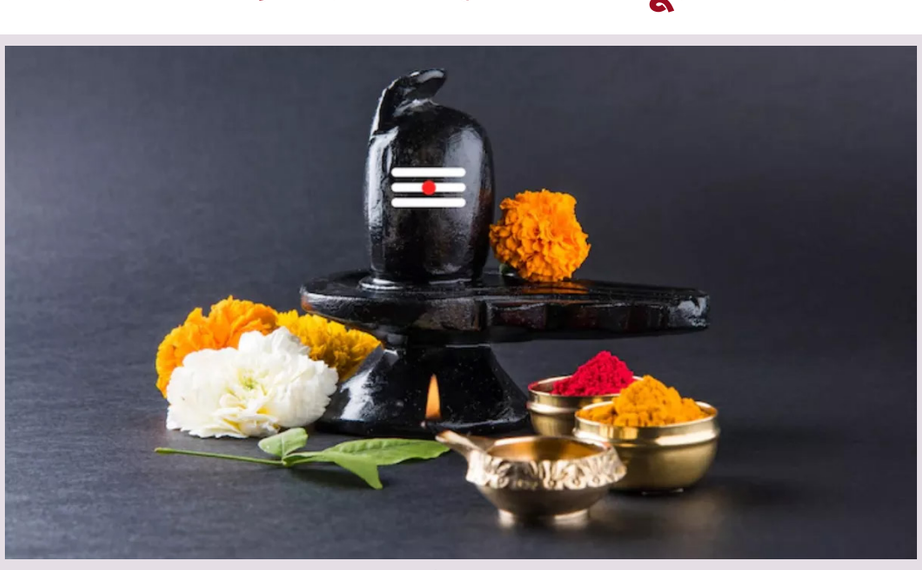

घर में शिवलिंग स्थापित करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि पूरे वातावरण को शांत, पवित्र और ऊर्जावान बनाने वाला एक आध्यात्मिक अनुभव माना जाता है। शिवभक्त अक्सर यह इच्छा रखते हैं कि उनके घर के मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग हो, ताकि वे रोज़ भगवान शिव का ध्यान, पूजन और जलाभिषेक कर सकें। हिंदू धर्म में यह मान्यता प्रचलित है कि जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है, वहाँ दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और उस स्थान पर रहने वालों के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और मानसिक शांति का वास होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शिवलिंग स्थापित करने के साथ कुछ महत्वपूर्ण नियम जुड़े होते हैं, जिन्हें न मानने पर न सिर्फ पूजा निष्फल हो सकती है, बल्कि अनचाहे परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसलिए अगर आप घर में शिवलिंग स्थापित करने जा रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि आप इन नियमों का पालन करें, ताकि आपकी श्रद्धा और साधना दोनों सफल हो सकें।

घर में शिवलिंग रखने की सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे किस दिशा में रखा जा रहा है। प्राचीन वास्तु ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि शिवलिंग की स्थापना उत्तर दिशा या ईशान कोण, यानी उत्तर-पूर्व दिशा में की जानी चाहिए। यह दिशाएँ शिव तत्व की ऊर्जा के सबसे अनुकूल मानी जाती हैं। इन्हीं दिशाओं में ऊर्जा का प्राकृतिक प्रवाह सबसे शांत और सकारात्मक रहता है। यदि शिवलिंग को इन दिशाओं में स्थापित किया जाए, तो घर के वातावरण में शांति, सद्भाव और सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही, जलाधारी की दिशा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। जलाधारी वह भाग होती है जिससे जल बाहर निकलता है और इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही रखा जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जलाभिषेक के दौरान बहने वाला जल अशुद्धियों को बाहर निकालता है और इसलिए इसका प्रवाह शुभ दिशाओं में होना चाहिए। शिवलिंग के आकार को लेकर भी बहुत से लोग अनभिज्ञ होते हैं। घर में बहुत बड़ा शिवलिंग रखना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि उसका पूजन करना कठिन हो जाता है और यह गृहस्थ जीवन के लिए अनुकूल नहीं माना गया है। दूसरी ओर, बहुत छोटा शिवलिंग ऊर्जा के स्तर पर उतना प्रभावकारी नहीं होता। इसलिए वास्तु और शास्त्र दोनों में यह बताया गया है कि घर में अंगूठे के आकार का शिवलिंग सबसे शुभ माना जाता है। यह आकार ऊर्जा संतुलन और गृहस्थ जीवन की मर्यादा, दोनों के लिए उपयुक्त होता है। कई लोग भावनावश घर में दो या इससे अधिक शिवलिंग रख लेते हैं, लेकिन यह वास्तु के अनुसार उचित नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि घर में केवल एक ही शिवलिंग होना चाहिए। एक से अधिक शिवलिंग रखना गृहस्थ जीवन में असंतुलन, मानसिक तनाव या वास्तुदोष का कारण बन सकता है। शिवलिंग एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक है और इसलिए इसका अधिक होना ऊर्जा के अतिप्रवाह जैसा समझा जाता है, जो दैनिक जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होता।

इसी तरह, यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी खंडित या टूटा हुआ शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ शिवलिंग अपशकुन माना जाता है और इससे जीवन में बाधाएँ और नकारात्मक प्रभाव आ सकते हैं। यदि किसी कारणवश आपका शिवलिंग खंडित हो जाए, तो भगवान से क्षमा मांगकर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा करने से दोष समाप्त हो जाते हैं और वातावरण फिर से शुद्ध हो जाता है। अंत में, शिवलिंग की स्थापना के कुछ सामान्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। शिवलिंग को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे हमेशा किसी चौकी, पाट या स्वच्छ ऊँचे स्थान पर ही स्थापित करना चाहिए। इसके साथ ही, शिवलिंग को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक तनाव, अस्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि बेडरूम विश्राम का स्थान होता है और शिवलिंग अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र है। इन दोनों का एक स्थान पर होना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। ध्यान, श्रद्धा और सही नियमों का पालन करके जब घर में शिवलिंग स्थापित किया जाता है, तो यह केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं रह जाता, बल्कि घर की किस्मत बदलने वाला एक दिव्य केंद्र बन जाता है। जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करता है, उसके जीवन में धीरे-धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। शांति बढ़ती है, मन स्थिर होता है और जीवन में नई ऊर्जा का प्रवेश होता है। भगवान शिव की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है जो सही विधि से शिवलिंग की स्थापना और पूजा करते हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया; मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की

- प्रधानमंत्री ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की टीम के साथ बातचीत की
- प्रधानमंत्री ने बुलेट ट्रेन के कार्यान्वयन से प्राप्त सीखों को दस्तावेज़ीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला
- प्रधानमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब राष्ट्र के लिए काम करने और कुछ नया योगदान देने की भावना जागृत होती है, तो यह अत्यधिक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है

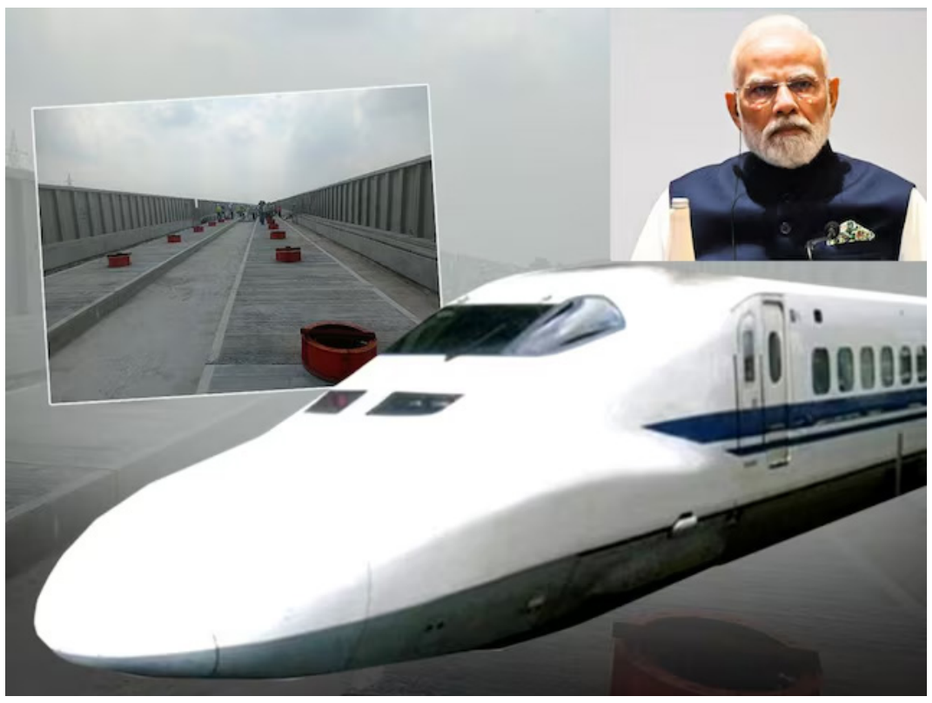

(जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना की टीम से भी बातचीत की और गति तथा समय सारिणी के लक्ष्यों के पालन सहित परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी ली। कर्मियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि परियोजना बिना किसी कठिनाई के सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। केरल की एक इंजीनियर ने गुजरात के नवसारी स्थित नॉइज़ बैरियर फ़ैक्टरी में काम करने का अपना अनुभव साझा किया, जहाँ सरिया के पिंजरों की वेल्डिंग के लिए रोबोटिक इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं। श्री मोदी ने उनसे पूछा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन के निर्माण के अनुभव को उन्होंने व्यक्तिगत रूप से कैसा महसूस किया और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में वे अपने परिवारों के साथ क्या साझा करती हैं। उन्होंने देश की पहली बुलेट ट्रेन में योगदान देने पर गर्व व्यक्त किया और इसे अपने परिवार के लिए एक "ड्रीम प्रोजेक्ट" और "गर्व का क्षण" बताया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र सेवा की भावना पर विचार करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि जब राष्ट्र के लिए काम करने और कुछ नया योगदान देने की भावना जागृत होती है, तो यह अत्यधिक प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। उन्होंने भारत की अंतरिक्ष यात्रा के साथ तुलना करते हुए याद दिलाया कि देश का पहला उपग्रह प्रक्षेपित करने वाले वैज्ञानिकों को कैसा महसूस हुआ होगा और आज कैसे सैकड़ों उपग्रह प्रक्षेपित किए जा रहे हैं।

बेंगलुरु की एक अन्य कर्मचारी, श्रुति, मुख्य इंजीनियरिंग प्रबंधक के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कठोर डिज़ाइन और इंजीनियरिंग नियंत्रण प्रक्रियाओं के बारे में बताया। श्रुति ने बताया कि कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में, उनकी टीम फायदे और नुकसान का मूल्यांकन करती है, समाधानों की पहचान करती है और दोषरहित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विकल्पों की खोज करती है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि यदि यहाँ प्राप्त अनुभवों को ब्लू बुक की तरह दर्ज और संकलित किया जाए, तो देश बुलेट ट्रेनों के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत को बार-बार प्रयोग करने से बचना चाहिए और इसके बजाय मौजूदा मॉडलों से सीखों को दोहराना चाहिए। श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि अनुकरण तभी सार्थक होगा जब यह स्पष्ट समझ हो कि कुछ कदम क्यों उठाए गए। उन्होंने आगाह किया, कि अनुकरण बिना किसी उद्देश्य या दिशा के हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे रिकॉर्ड बनाए रखने से भविष्य के विद्यार्थियों को लाभ हो सकता है और राष्ट्र निर्माण में योगदान मिल सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, "हम अपना जीवन यहीं समर्पित करेंगे और देश के लिए कुछ मूल्यवान छोड़ जाएँगे।"

एक कर्मचारी ने एक कविता के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता को भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया, जिस पर प्रधानमंत्री ने उनके समर्पण की प्रशंसा और सराहना की।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव इस दौरे के अवसर पर मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ने मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (एमएएचएसआर) की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया। यह भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से एक है और देश के हाई-स्पीड कनेक्टिविटी के युग में प्रवेश का प्रतीक है।

एमएएचएसआर लगभग 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 352 किलोमीटर गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली में और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में शामिल है। यह कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई सहित प्रमुख शहरों को जोड़ेगा, जो भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे में एक परिवर्तनकारी कदम है।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत इंजीनियरिंग तकनीकों से निर्मित इस परियोजना में 465 किलोमीटर (मार्ग का लगभग 85 प्रतिशत) पुलों पर बना है, जिससे न्यूनतम भूमि व्यवधान और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब तक 326 किलोमीटर पुल निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और 25 में से 17 नदी पुलों का निर्माण हो चुका है।

बुलेट ट्रेन परियोजना के पूरा होने पर, मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को लगभग दो घंटे तक कम कर देगी, जिससे अंतर-शहर यात्रा तेज, आसान और अधिक आरामदायक बनकर क्रांति ला देगी। इस परियोजना से पूरे कॉरिडोर पर व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और क्षेत्रीय विकास को गति मिलने की संभावना है। सूरत-बिलिमोरा खंड, लगभग 47 किलोमीटर लंबा है और यह निर्माण कार्य के अंतिम चरण में है, जिसमें सिविल कार्य और ट्रैक बिछाने का काम पूर्ण रूप से पूरा हो चुका है। सूरत स्टेशन का डिज़ाइन शहर के विश्व प्रसिद्ध हीरा उद्योग से प्रेरित है, जो सुंदरता और कार्यक्षमता दोनों को दर्शाता है। स्टेशन को यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान देते हुए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें विशाल प्रतीक्षालय, शौचालय और खुदरा दुकानें हैं। यह सूरत मेट्रो, सिटी बसों और भारतीय रेलवे नेटवर्क के साथ निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा।

द्वितीय वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) का फोकस कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र पर

- यह रीजनल कॉन्फ्रेंस 8-9 जनवरी 2026 को राजकोट में आयोजित की जाएगी
- द्वितीय VGRC से पूर्व दिसंबर 2025 में 11 जिला-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे

(जीएनएस)। गांधीनगर : माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल के सशक्त नेतृत्व में गुजरात सरकार मेहसाणा, राजकोट, सूरत और वडोदरा में चार वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंसेस (VGRC) का आयोजन कर रही है।

ये कॉन्फ्रेंसेस जनवरी 2027 में प्रस्तावित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से पहले आयोजित की जा रही हैं, ताकि प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट क्षमताओं को वैश्विक मंच पर बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया जा सके। हर कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास की गति को और तेज करना, निवेश के नए अवसरों को बढ़ावा देना तथा समावेशी और संतुलित प्रगति को सुदृढ़ बनाना है।

इसके साथ ही, प्रत्येक रीजनल कॉन्फ्रेंस से पूर्व जिला-स्तरीय एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें स्थानीय अवसरों, सफलता की कहानियों, नवाचारों और उभरती संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर विकास की नई दिशा और ऊर्जा सुनिश्चित हो सके।

इसी क्रम में, द्वितीय वाइब्रेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) का आयोजन 8 और 9 जनवरी 2026 को राजकोट में होने जा रहा है। स्थानीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने के उद्देश्य के साथ यह सम्मेलन व्यापक बाज़ार पहचान, रणनीतिक सहयोग और नई साझेदारियों को प्रोत्साहित करने का सशक्त मंच प्रदान करेगा।

कॉन्फ्रेंस में कृषि, खनन, पर्यटन और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रतिभागियों के लिए MSME कॉन्क्लेव, रिवर्स बायर-सेलर मीट (RBSM), प्रदर्शनी और ट्रेड फेयर जैसी गतिविधियाँ भी होंगी, जो निवेश, नेटवर्किंग और व्यवसायिक अवसरों को विस्तार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी। साथ ही, दिसंबर 2025 के दौरान अमरेली, भावनगर, बोटाद, देवभूमि द्वारका, गिर-सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, मोरबी, पोरबंदर और सुरेंद्रनगर जिलों में जिला-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य स्थानीय क्षमताओं, अवसरों और पहलों को नए स्तर पर प्रसारित करना है।

उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2025 में नॉर्थ गुजरात के मेहसाणा में प्रथम वाइब्रेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) का अत्यंत सफल आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप 1,264 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें कुल 3.25 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश शामिल हैं—जो क्षेत्र की विकास संभावनाओं और निवेशकों के उत्साह का प्रमाण है।

दो दिवसीय इस कॉन्फ्रेंस में उल्लेखनीय सहभागिता रही, जिसमें 29,000 से अधिक पंजीकृत प्रतिभागियों ने भाग लिया। साथ ही, 80 से अधिक देशों से आए 440 से अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को वैश्विक पहचान और व्यापक सहयोग का नया आयाम प्रदान किया। वैश्विक और घरेलू सहयोग की उत्कृष्ट मिसाल पेश करते हुए इस कॉन्फ्रेंस में 160 से अधिक बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B) और 100 से अधिक बिज़नेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकों का सफल आयोजन किया गया, जिन्होंने नई साझेदारियों, निवेश संभावनाओं और औद्योगिक सहयोग को मजबूत आधार प्रदान किया। इसके साथ ही, 410 से अधिक प्रदर्शकों ने अपने नवाचारों और उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिनमें 170 से अधिक MSMEs और स्टार्टअप्स की उल्लेखनीय भागीदारी रही।

उद्यमी मेले में 9,000 से अधिक उद्यमियों को 900 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन सहायता प्रदान की गई, जिससे स्थानीय उद्यमिता को नई ऊर्जा मिली। भारतनेक्स्ट स्टार्टअप पिचिंग फेस्टिवल के दौरान 41.56 करोड़ के निवेश की घोषणा ने नवाचार-आधारित स्टार्टअप इकोसिस्टम को और सशक्त बनाया। वहीं, RBSM (रिवर्स बायर-सेलर मीट) में 850 से अधिक गुजरात-आधारित विक्रेताओं के साथ 2,200 से अधिक व्यापारिक बैठकें आयोजित की गईं, जिनसे 500 करोड़ से अधिक की निर्यात-उन्मुख व्यापारिक पूछताछ उत्पन्न हुई। यह उपलब्धियाँ न केवल गुजरात की उद्यमशीलता क्षमता को उजागर करती हैं, बल्कि राज्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी नए आयाम देती हैं।

आगामी 8–9 जनवरी 2026 को राजकोट में आयोजित होने वाला द्वितीय वाइब्रेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) सौराष्ट्र और कच्छ दोनों क्षेत्रों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को नई गति देगा। कच्छ और सौराष्ट्र अपनी भौगोलिक विविधता, समृद्ध प्राकृतिक विरासत और जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं के लिए विशेष पहचान रखते हैं, जहाँ पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक आर्थिक प्रगति का संतुलित मेल देखने को मिलता है। यह क्षेत्र अपने समुद्री इतिहास और कांडला व मुंद्रा जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों के कारण देश के प्रमुख लॉजिस्टिक्स, व्यापार और ग्रीन शिपिंग केंद्रों में से एक है। पेट्रोकेमिकल्स, सेरामिक्स और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में यह प्रदेश अग्रणी रहा है, जिसे अत्याधुनिक अवसंरचना और नवाचार-प्रधान नीतियों का मजबूत सहयोग प्राप्त है। साथ ही, आध्यात्मिक एवं विरासत पर्यटन सर्किट यहां परंपरा और व्यवसाय-उन्मुख गतिविधियों के बीच एक अनूठा और संतुलित समन्वय स्थापित करते हैं।

यह सम्मेलन न केवल क्षेत्र की मौजूदा क्षमताओं को नए अवसरों से जोड़ने का कार्य करेगा, बल्कि निवेश, नवाचार और सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में भी उभरेगा।

राजकोट में आयोजित होने वाले द्वितीय वाइब्रेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस (VGRC) में कच्छ और सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए कई उच्च-प्राथमिकता वाले सेक्टरों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनमें सेरामिक्स, इंजीनियरिंग, पोर्ट्स एवं लॉजिस्टिक्स, मत्स्य उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, एग्रो एवं फूड प्रोसेसिंग, खनिज, ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम, कौशल विकास, स्टार्टअप्स, MSMEs, पर्यटन एवं संस्कृति जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं।

इसके साथ ही, सेरामिक, कॉटन और प्लास्टिक के निर्यात, ब्रास कंपोनेंट्स, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, तटीय पर्यटन और अन्य उभरते क्षेत्रों में उपलब्ध उत्कृष्ट व्यावसायिक अवसरों को भी इस सम्मेलन के माध्यम से और अधिक गहनता से समझा, प्रदर्शित और विस्तारित किया जाएगा। यह सम्मेलन इन सेक्टरों में निवेश, नवाचार और क्षेत्रीय विकास के नए द्वार खोलने का महत्वपूर्ण मंच साबित होगा।

ऊर्जा सुरक्षा पर भारत का जोर, कोयला आयात बढ़ा

नई दिल्ली। भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सितंबर महीने में देश का कोयला आयात 13.54% बढ़कर 22.05 मिलियन टन (एमटी) पर पहुंच गया। इसमें 13.90 एमटी गैर-कोकिंग कोयला और 4.50 एमटी इस्पात उद्योग में इस्तेमाल होने वाला कोकिंग कोयला शामिल है।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इस साल सितंबर में गैर-कोकिंग कोयले का आयात पिछले साल के 13.24 एमटी से थोड़ा बढ़कर 13.90 एमटी दर्ज किया गया। वहीं कोकिंग कोयले का आयात 3.39 एमटी से बढ़कर 4.50 एमटी हो गया, जो स्टील सेक्टर की मजबूत मांग को दर्शाता है।

अप्रैल–सितंबर 2025 की अवधि में गैर-कोकिंग कोयले का कुल आयात घटकर 86.06 एमटी रहा, जबकि कोकिंग कोयले का आयात बढ़कर 31.54 एमटी पहुंच गया। यह जानकारी एमजंक्शन सर्विसेज ने दी है, जो टाटा स्टील और सेल की संयुक्त बी2बी ई-कॉमर्स कंपनी है।

एमजंक्शन की एमडी और सीईओ विनया वर्मा का कहना है कि त्योहारों से पहले बढ़ी खरीदारी और इस्पात मिलों द्वारा सर्दियों के स्टॉक की तैयारी ने कोयला आयात को बढ़ाया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि औद्योगिक कोयले और इस्पात की मजबूत मांग आने वाले महीनों में बिजली क्षेत्र की मौसमी सुस्ती को पीछे छोड़ सकती है।

ऊर्जा मिश्रण को विविध बनाने के प्रयास में, एनटीपीसी देशभर में कई नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी कर रही है। कंपनी 700 मेगावॉट, 1,000 मेगावॉट और 1,600 मेगावॉट क्षमता वाली परमाणु परियोजनाओं पर काम करेगी।

एनटीपीसी फिलहाल गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में जमीन के विकल्प तलाश रही है। अंतिम साइटों को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड (AERB) की मंजूरी के बाद ही तय किया जाएगा।

कंपनी जरूरी कच्चे माल को सुनिश्चित करने के लिए विदेशों में यूरेनियम संपत्तियों के अधिग्रहण की संभावनाएं भी तलाश रही है।

बीएसई की शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों की मार्केट कैप दो लाख करोड़ से अधिक बढ़ी; एयरटेल सबसे बड़ी लाभकर्ता

(जीएनएस)। नई दिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में पिछले सप्ताह जारी मजबूती का सीधा असर देश की सबसे बड़ी कंपनियों के बाजार मूल्य पर पड़ा। बीएसई की टॉप-10 मार्केट कैप वाली कंपनियों में से आठ ने कुल मिलाकर दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की। इस तेजी का सबसे बड़ा फायदा भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज को हुआ, जबकि बजाज फाइनेंस और एलआईसी को भारी गिरावट का सामना करना पड़ा।

बाजार में निवेशकों की बढ़ी उम्मीदों, वैश्विक संकेतों में सुधार और घरेलू आर्थिक मोर्चे पर सकारात्मक माहौल ने प्रमुख कंपनियों के शेयरों को मजबूत बनाए रखा। परिणामस्वरूप एयरटेल, रिलायंस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर—इन आठ कंपनियों के कुल मार्केट कैप में 2,05,185 करोड़ रुपये का इजाफा देखा गया। दूसरी ओर केवल दो बड़ी कंपनियों—बजाज फाइनेंस और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)—के मूल्य में संयुक्त रूप से 39,414 करोड़ रुपये की कमी आई।

सप्ताह की सबसे बड़ी छलांग एयरटेल ने लगाई। 10 से 14 नवंबर के बीच इसके बाजार पूंजीकरण में 55,652 करोड़ रुपये की तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे इसका कुल मार्केट कैप 11,96,701 करोड़ रुपये पहुंच गया। ठीक उसके पीछे रिलायंस इंडस्ट्रीज रही, जिसने 54,942 करोड़ रुपये की मजबूती के साथ 20,55,380 करोड़ रुपये का स्तर हासिल किया। यह न केवल सप्ताह की दूसरी सबसे बड़ी बढ़त रही, बल्कि इसे मार्केट कैप के हिसाब से देश की सबसे मूल्यवान कंपनी की स्थिति भी बनाए रखी।

आईटी की दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने भी बढ़त का मजबूत प्रदर्शन किया और उसका बाजार मूल्य 40,757 करोड़ रुपये बढ़कर 11,23,416 करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक ने 20,834 करोड़, एसबीआई ने 10,523 करोड़ और इंफोसिस ने 10,448 करोड़ रुपये की बढ़त हासिल की। एचडीएफसी बैंक का बाजार मूल्य भी 9,149 करोड़ बढ़कर 15,20,524 करोड़ रुपये हो गया। उपभोक्ता उत्पाद कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 2,878 करोड़ की मामूली लेकिन सकारात्मक बढ़त दर्ज की।

इसके उलट सप्ताह बजाज फाइनेंस के लिए काफी भारी साबित हुआ। इसका मार्केट कैप 30,148 करोड़ रुपये घटकर 6,33,573 करोड़ रुपये पर आ गया। बीमा क्षेत्र के दिग्गज LIC को भी झटका लगा और उसका बाजार मूल्य 9,266 करोड़ रुपये घटकर 5,75,100 करोड़ रुपये रह गया।

सप्ताह के अंत में मार्केट कैप के आधार पर शीर्ष कंपनियों की रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज 20.55 लाख करोड़ रुपये के साथ पहले स्थान पर रही। उसके बाद एचडीएफसी बैंक 15.20 लाख करोड़, भारती एयरटेल 11.96 लाख करोड़, टीसीएस 11.23 लाख करोड़, आईसीआईसीआई बैंक 9.80 लाख करोड़, एसबीआई 8.92 लाख करोड़, बजाज फाइनेंस 6.33 लाख करोड़, इंफोसिस 6.24 लाख करोड़, LIC 5.75 लाख करोड़ और हिंदुस्तान यूनिलीवर 5.70 लाख करोड़ रुपये के बाजार मूल्य के साथ क्रमशः शीर्ष 10 में शामिल रहे।

घरेलू बाजार में यह मजबूती आने वाले सप्ताह के लिए भी संकेतक मानी जा रही है, हालांकि वैश्विक स्तर पर तेल कीमतों, अमेरिकी बाजारों की चाल और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के रुझान पर निवेशकों की पैनी नजर बनी हुई है।

गुंटूर में नाबालिग छात्रा का अपहरण व दुष्कर्म,युवक ने पहनाया मंगलसूत्र, मां–दादी ने दिया साथ, पुलिस ने तीन गिरफ्तार

(जीएनएस)। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में दसवीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा के साथ अपहरण और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया है। मामले पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित दो महिला रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पिछले साल छात्रा किसी काम से प्रकाशम जिले के येरागोंडापलेम में अपने रिश्तेदारों के घर गई थी। वहीं उसकी मुलाकात नेल्लोर निवासी युवक बन्नी से हुई। बन्नी ने छात्रा का फोन नंबर लेकर उससे लगातार संपर्क बनाए रखा और प्रेम के नाम पर उसे फंसाने की कोशिश करता रहा। बीते 10 अक्टूबर को, बन्नी अपने एक दोस्त के साथ छात्रा के स्कूल पहुंचा और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इसके बाद उसने छात्रा को पांच दिनों तक अपने पास रखा। 15 अक्टूबर को, आरोपी ने छात्रा के गले में हल्दी की गांठ (मंगलसूत्र) बांध दिया। इस दौरान जब डरी हुई छात्रा ने घर जाने की इच्छा जताई, तो बन्नी की मां और दादी ने उसे रोक लिया। उन्होंने छात्रा को अपने घर में रखा और उसी रात बन्नी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने सुनाई आपबीती

अगले दिन, 16 अक्टूबर को पीड़िता के जोर देने पर बन्नी उसे गुंटूर ग्रामीण मंडल में उसके घर ले आया। इस बीच, छात्रा के माता-पिता द्वारा पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के कारण पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। घर लौटने के बाद, पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरी घटना की जानकारी दी, जिन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया।

पुलिस ने दर्ज की शिकायत

मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी जुटाई और लड़की की शिकायत के आधार पर पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर बन्नी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि, बलात्कार की जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी की मां, दादी और दोस्त ने उसकी मदद की थी। पुलिस ने बन्नी की मां और दादी को भी गिरफ्तार कर लिया है और अपराध में शामिल एक अन्य फरार दोस्त की तलाश जारी है। मामले को लेकर गुंटूर दक्षिण क्षेत्र के डीएसपी भानोदय ने कहा कि आरोपी के खिलाफ शख्त कार्रवाई की जाएगी।

"इलाज के तानों से तंग आकर बेटे ने ली मां-बाप की जान, कटनी में कुल्हाड़ी से किया दोहरा कत्ल"

(जीएनएस)। मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले में सामने आया दोहरा हत्याकांड पूरे क्षेत्र में दहशत और सन्नाटा छोड़ गया है। खेत के पास पति-पत्नी के क्षत-विक्षत शव मिलने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की, तो शुरुआत में किसी बाहरी हमले की आशंका जताई जा रही थी। परंतु मात्र 24 घंटे के भीतर खुलासा होने पर चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई—इन दोनों की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उनके अपने बेटे ने की थी। हत्या का तरीका, उसका कारण और घटना के समय घर में मौजूद नाबालिग बेटी की आंखों के सामने unfold हुआ पूरा घटनाक्रम किसी दर्दनाक पारिवारिक त्रासदी से कम नहीं था।

कटनी के बड़वारा थाना क्षेत्र के निगैरह गांव में रहने वाले लल्लू कुशवाह और उनकी पत्नी प्रभा बाई कुशवाह खेत की चौकीदारी करते थे। दोनों रात में खेत के पास ही बने एक छोटे से कमरे में रहते थे और वहीं सोया करते थे। बीते दिनों दोनों संदिग्ध हालात में मृत मिले। उनके शरीर पर कुल्हाड़ी के गहरे वार थे, जो किसी बेरहम और गुस्से से भरी कार्रवाई का संकेत दे रहे थे। पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो देखा कि हत्या बेहद नजदीक से और सोते हुए समय की गई थी। एडिशनल एसपी डॉ. संतोष डेहरिया के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतक दंपति का अपने बेटे अभिषेक से लंबे समय से विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले अभिषेक का एक गंभीर एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसके इलाज पर लगभग डेढ़ लाख रुपये का खर्च आया था। पिता लल्लू कुशवाह ने अपनी सामर्थ्य से अधिक खर्च कर इलाज करवाया था, लेकिन घटना के बाद वह अपने बेटे को इसी बात के ताने देने लगे थे। उनके लगातार ताने और डांट-फटकार ने बेटे के मन में गुस्सा और घुटन पैदा कर दी थी।

घटना की रात भी घर में मामूली विवाद हुआ था। बताया जाता है कि रात के समय जब सभी सो रहे थे, तभी अभिषेक ने अचानक कुल्हाड़ी उठाई और अपने पिता तथा सौतेली मां पर वार करना शुरू कर दिया। वार इतने तेज़ और क्रूर थे कि पति-पत्नी को बचाव का कोई मौका नहीं मिला। दोनों घटनास्थल पर ही ढेर हो गए। आरोपी घटना के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया।

सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि वारदात को मृतक की नाबालिग बेटी ने अपनी आंखों से होते देखा। मासूम बच्ची डर और सदमे में थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाते हुए सुबह पड़ोसियों को बताया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बच्ची के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी बेटे अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया।

पूरी घटना ने गांव में भय और स्तब्धता पैदा कर दी है। एक ओर जहां ग्रामीण इस पारिवारिक हत्या से दुखी और हैरान हैं, वहीं ताने-बाने में छिपे तनाव, परिवारों में बढ़ते मनोवैज्ञानिक दबाव और संवादहीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक बेटा किस मानसिक स्थिति में अपने ही माता-पिता की जान ले सकता है।

"प्रेम–प्रसंग ने ली खौफनाक मोड़: दुमका में प्रेमी ने पत्नी संग मिलकर विधवा प्रेमिका को जिंदा जलाया"

(जीएनएस)। दुमका से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहशत से भर दिया है और यह सवाल फिर खड़ा कर दिया है कि प्रेम, जब जुनून और हिंसा में बदल जाए, तो इंसान कितनी हदें पार कर सकता है। झारखंड के दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक शादीशुदा प्रेमी ने अपनी विधवा प्रेमिका को न केवल पीड़ा और धोखे का सामना कराया, बल्कि प्रेम–प्रसंग के विवाद में वह हैवानियत के उस स्तर तक पहुंच गया जहां उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर महिला को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा आग के हवाले कर दिया। यह घटना 13 नवंबर की रात को घटी, जब सीतासाल गांव की रहने वाली विधवा माकू मुर्मू अपने घर पर थी।

माकू मुर्मू और मोंगला देहरी के बीच पिछले करीब तीन वर्षों से प्रेम–संबंध थे। मोंगला का पहले से विवाहित होना अक्सर इस रिश्ते में तनाव और झगड़े का कारण बनता था। कई बार विवाद इतना बढ़ जाता था कि आसपास के लोग बीच-बचाव करते थे। लेकिन उस रात स्थिति बिल्कुल अलग थी। मोंगला अपनी पत्नी के साथ प्रेमिका के घर पहुंचा और वहां फिर बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि मोंगला देहरी और उसकी पत्नी ने मिलकर पेट्रोल की बोतल खोली और माकू मुर्मू पर पूरी तरह पेट्रोल उड़ेल दिया। महिला कुछ समझ पाती, उससे पहले ही दोनों ने उसे आग के हवाले कर दिया। चीख़ते–चिल्लाते हुए माकू अपने घर से बाहर भागी, लेकिन तब तक आग ने उसका लगभग पूरा शरीर अपनी चपेट में ले लिया था।

गांव वाले दौड़े, पर जब तक आग बुझाई जा सकी, तब तक उसकी हालत बेहद गंभीर हो चुकी थी। आनन–फानन में परिजनों ने उसे पश्चिम बंगाल के बर्दवान मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाने की कोशिश में जुटे हैं। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और शरीर का बड़ा हिस्सा झुलस चुका है।

इस पूरी घटना के बाद एक तरफ गांव में भय का माहौल है, तो दूसरी तरफ माकू की मां फुलमनी हांसदा ने शिकारीपाड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायत के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और मुख्य आरोपी मोंगला देहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पत्नी, जो इस खौफनाक वारदात में बराबर की आरोपी है, फिलहाल फरार है। पुलिस लगातार उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।

दुमका में प्रेम–प्रसंग से जुड़े हिंसक मामलों की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले गुमला जिले में 19 वर्षीय युवक ने विवाद के बाद अपनी पांच महीने की गर्भवती नाबालिग प्रेमिका का गला रेतकर हत्या कर दी थी। ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि व्यक्तिगत रिश्तों में उभर रहा अविश्वास, गुस्सा और हिंसा किस तरह पूरे समाज में क्रूरता का जहर घोल रहे हैं।

बिहार में नई सरकार की तस्वीर साफ: BJP को 16, JDU को CM सहित 14 मंत्री, चिराग पासवान की पार्टी को भी बड़ा फायदा

(जीएनएस)। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की भारी और ऐतिहासिक जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। पटना की राजनीतिक फिज़ा में नई सत्ता टीम को लेकर हलचल जारी है, और सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल का खाका लगभग अंतिम रूप ले चुका है। एनडीए के तीन प्रमुख स्तंभ – भाजपा, जदयू और लोजपा (रामविलास) – के बीच मंत्रालयों के बंटवारे पर सहमति बनने लगी है, और बहुत जल्द नई सरकार पटना में शपथ लेगी।

सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 15 से 16 मंत्री पद आने की संभावना है। पार्टी के रणनीतिकार चुनाव नतीजों के बाद से ही अपने संभावित मंत्रियों की सूची तैयार कर रहे हैं। भाजपा ने पार्टी के भीतर जो संकेत दिए हैं, उनसे यह साफ है कि सम्राट चौधरी और दिलीप जायसवाल जैसे नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियाँ देकर मंत्रिमंडल में प्रमुख भूमिका दी जा सकती है। पार्टी राज्य में अपनी सत्ता साझेदारी की स्थिति इस बार सबसे मजबूत देख रही है और उसे मंत्रिमंडल में व्यापक दायरा मिलने की संभावना है।

उधर, एनडीए में नीतीश कुमार की जदयू को मुख्यमंत्री के साथ 14 मंत्रियों की जगह मिलने की चर्चा है। शिकस्त झेल चुकी महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ खड़े हैं और इस साझेदारी की मजबूती बनाने के लिए लगातार भाजपा नेतृत्व से बैठकें होती रही हैं। दोनों दलों के बीच विभागों के बंटवारे को लेकर गहन विचार-विमर्श हुआ है, ताकि आने वाले वर्षों में सरकार सुचारू रूप से चल सके। सूत्र बताते हैं कि कुछ पुराने चेहरों की वापसी और कुछ नए नेताओं की एंट्री पर भी शीर्ष नेतृत्व की सहमति बनती जा रही है।

लोजपा (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान इस बार सबसे बड़े लाभार्थी के रूप में उभर रहे हैं। खबर है कि उनकी पार्टी से तीन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। चिराग ने चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए के लिए आक्रामक और रणनीतिक भूमिका निभाई, जिसका सीधा लाभ अब उन्हें सरकार में मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस निर्णय से एनडीए के भीतर नेतृत्व संतुलन और बेहतर होता दिखेगा, क्योंकि युवा चेहरे को प्रमुख स्थान देना भाजपा और जदयू दोनों के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद है।

इसके अलावा जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियों से भी एक-एक विधायक को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। एनडीए का प्रयास है कि वह सत्ता में पारदर्शी और सर्वसमावेशी गठबंधन की छवि पेश करे। यह भी जानकारी सामने आई है कि आने वाले समय में राज्यसभा की सीटों पर भी एनडीए के सहयोगियों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जिससे गठबंधन की एकजुटता और सार्वजनिक रूप से मजबूत दिखे।

पटना में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ युद्धस्तर पर चल रही हैं। गांधी मैदान को 17 से 20 नवंबर तक आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, जहां विशाल मंच और सुरक्षा इंतज़ाम तेज़ी से तैयार किए जा रहे हैं। सबसे अधिक संभावना 19 या 20 नवंबर की तारीख की मानी जा रही है, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर अपने नए मंत्रिमंडल को राजभवन में प्रस्तुत करेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 202 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल किया। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, जबकि महागठबंधन 35 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सका। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी 28 सीटों पर मैदान में उतरी, परंतु कोई सीट नहीं जीत पाई। AIMIM ने इस बार 5 सीटों पर सफलता हासिल की, जो इस चुनाव का एक दिलचस्प पक्ष रहा।

नई सरकार के गठन के साथ बिहार की राजनीति नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि मजबूत बहुमत के बावजूद एनडीए के भीतर सत्ता संतुलन कैसे कायम रहता है और विकास के एजेंडे को लेकर आने वाले वर्षों में सरकार किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभाती है।

“विपक्ष दिशाहीन इसलिए कमजोर” — रालोद राष्ट्रीय अधिवेशन में जयंत चौधरी दोबारा अध्यक्ष चुने गए

(जीएनएस)। मथुरा। राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के राष्ट्रीय अधिवेशन में रविवार को पार्टी ने एक बार फिर जयंत सिंह चौधरी पर अपना भरोसा जताते हुए उन्हें सर्वसम्मति से आगामी तीन वर्षों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। कोसीकलां में आयोजित इस अधिवेशन में पूरे देश से आए प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। जयंत चौधरी ने अपने संबोधन की शुरुआत मथुरा की जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए की और कहा कि इस धरती ने उन्हें पहली बार संसद में भेजकर जो सम्मान दिया, उसे वह जीवनभर नहीं भूलेंगे। अधिवेशन के दौरान जयंत चौधरी ने वर्तमान राजनीतिक हालात पर तीखी टिप्पणी करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि “देश का विपक्ष आज दिशाहीन है। उसके पास न नेतृत्व है और न ही किसी मुद्दे पर स्पष्ट नीति। इसी वजह से वह जनता का भरोसा खो रहा है और लगातार कमजोर होता जा रहा है।”

उन्होंने कहा कि रालोद न केवल मजबूत राजनीतिक दिशा रखता है बल्कि एनडीए के सहयोगी के रूप में केंद्र सरकार के विकास के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी उनके लिए गर्व और विश्वास का विषय है।

अपने भाषण में उन्होंने महिला शक्ति के महत्व पर विशेष जोर दिया और कहा कि आधी आबादी को राजनीति और समाज में सशक्त किए बिना देश का विकास अधूरा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि महिलाओं को शीघ्र ही आरक्षण का लाभ मिलेगा और रालोद संगठन में भी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि महिलाएँ नेतृत्व में आगे आएंगी तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में मजबूती और सामाजिक परिवर्तन दोनों तेज होंगे।

उन्होंने किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि मथुरा की छाता चीनी मिल, जो वर्षों से बंद पड़ी है, उसे चालू कराना बेहद आवश्यक है। मुख्यमंत्री द्वारा गन्ने के समर्थन मूल्य को 400 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने को उन्होंने महत्वपूर्ण और किसान हितैषी कदम बताया। साथ ही उन्होंने रालोद को जमीनी स्तर पर और मज़बूत करने, नए सदस्यों को जोड़ने और किसान-युवा- महिलाओं के मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने की अपील की। उन्होंने घोषणा की कि पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 125वीं जयंती को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा और देशभर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

अधिवेशन के दौरान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक—तीनों प्रमुख प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। राष्ट्रीय सचिव अनुपम मिश्रा ने बताया कि आर्थिक प्रस्ताव में किसानों को केंद्र में रखते हुए मंडी व्यवस्था, गन्ना मूल्य, ग्रामीण उद्योग और कृषि तकनीक सुधारों पर जोर दिया गया। सामाजिक प्रस्ताव में युवा रोजगार, महिला सुरक्षा और शिक्षा सुधार की बात रखी गई। वहीं राजनीतिक प्रस्ताव में भारत की वैश्विक भूमिका, विदेश नीति और केंद्र सरकार के सशक्त नेतृत्व की सराहना की गई।

अधिवेशन ने यह भी अपील की कि सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची सुधार में चुनाव आयोग का सहयोग करें, ताकि चुनावी प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी एवं विश्वसनीय बन सके।

रालोद के इस अधिवेशन ने न केवल जयंत चौधरी के नेतृत्व पर पार्टी की मुहर लगाई, बल्कि यह संकेत भी दिया कि पार्टी अपने पारंपरिक किसान आधार के साथ-साथ नई पीढ़ी और महिलाओं को जोड़कर भविष्य की राजनीति में नई जगह बनाने के लिए तैयार है।

“शादी के एक घंटे पहले खून साड़ी-पैसों पर विवाद ने ली दुल्हन की जान, भावनगर में दिल दहला देने वाली वारदात”

(जीएनएस)। गुजरात के भावनगर शहर में शनिवार की रात एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सभी को सन्न कर दिया। जहां कुछ ही देर बाद सात फेरे होने थे, वहीं एक कमरे में दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन की जान ले रहा था। यह घटना टेकरी चौक क्षेत्र में हुई, जहां शादी की तैयारियों के बीच अचानक चीख-पुकार मच गई और खुशियों का माहौल मिनटों में मातम में बदल गया। दुल्हन सोनी की हत्या उसके प्रेमी और होने वाले पति साजन ने सिर्फ इसलिए कर दी कि दोनों के बीच शादी की साड़ी और पैसों को लेकर बहस हो गई थी।

मामले की जांच में सामने आया कि सोनी और साजन पिछले डेढ़ साल से साथ रह रहे थे। परिवारों की आपत्तियों के बावजूद दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया था। शादी की लगभग सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं, मेहमान आने शुरू हो चुके थे और घरों में रंग-बिरंगी रोशनियां जगमगा रही थीं। लेकिन इसी बीच कमरे में साड़ी के चुनाव और शादी के खर्चे को लेकर दोनों के बीच बहस छिड़ गई। पुलिस के अनुसार झगड़ा अचानक इतना बढ़ गया कि साजन अपना आपा खो बैठा और गुस्से में लोहे की रॉड लेकर सोनी पर वार कर दिया। सोनी दर्द से कराहते हुए फर्श पर गिर गई, लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुका। उसने सोनी का सिर पकड़कर दीवार में जोर से पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

बाहर मौजूद परिवार को जब धमकियों और चीखों की आवाज सुनाई दी, तब वे कमरे तक पहुंचे। दरवाजा खोलने पर सामने खून से सना फर्श, टूटी वस्तुएं और सोनी की निःजीव लाश पड़ी थी। दूल्हा साजन वहां से भाग चुका था। शादी के लिए सजाए गए मंडप, फर्श पर बिखरे फूल, कुर्सियों पर रखे आधे-अधूरे उपहार और घर में लगी झालरें देखते ही देखते इस त्रासदी की गवाह बन गईं। जिन दीवारों पर थोड़ी देर पहले संगीत की गूंज सुनाई दे रही थी, अब वहीं मातम का सन्नाटा फैल चुका था।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। भावनगर के डीएसपी आर.आर. सिंघल ने बताया कि यह घटना क्रूरता की पराकाष्ठा है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शनिवार को ही सोनी और साजन का एक पड़ोसी से झगड़ा हुआ था और उसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई थी। अब हत्या की नई FIR दर्ज कर ली गई है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या विवाद वास्तव में सिर्फ साड़ी और पैसों का था या रिश्ते में पहले से मौजूद तनाव इस खूनखराबे का कारण बना। साजन की तलाश में पुलिस ने शहर के सभी निकास बिंदुओं पर अलर्ट जारी किया है। सोनी के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रिश्तेदारों का कहना है कि सोनी और साजन दोनों शादी को लेकर बेहद खुश थे और रिश्तों में किसी बड़े तनाव का अंदेशा नहीं था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा कि एक साधारण सा घरेलू झगड़ा एक युवती की जिंदगी छीन लेगा और शादी जैसा पावन दिन खून से दागदार हो जाएगा। टेकरी चौक के लोग भी इस घटना से हिल गए हैं और यह सवाल उठने लगे हैं कि प्रेम संबंधों में बढ़ते तनाव और क्षणिक आवेश किस तरह युवाओं को अंधे फैसलों की ओर धकेल रहे हैं।

भावनगर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में आएगा। यह घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन चुकी है और एक बार फिर यह सवाल सामने खड़ा कर रही है कि रिश्तों में संवाद की कमी और क्रोध किस प्रकार जीवन को पलभर में तबाह कर सकता है।

“संभल की शाही जामा मस्जिद में एएसआई टीम को रोका, कमेटी के दो सदस्य नामजद—सरकारी काम में बाधा डालने पर एफआईआर दर्ज”

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद एक अप्रत्याशित विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गई है। मस्जिद के संरक्षण कार्य की समीक्षा के लिए गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की टीम को निरीक्षण करने से रोक देने के मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी के दो सदस्यों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों सदस्यों ने न सिर्फ सरकारी टीम को मुख्य गुंबद के निरीक्षण से रोका बल्कि मौजूद अधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। यह घटना 8 अक्टूबर की है, जिसके बाद अब मामले ने कानूनी रूप ले लिया है और पुलिस ने कमेटी सदस्यों की तलाश शुरू कर दी है।

घटना के दिन एएसआई मेरठ मंडल के अधिकारी विनोद कुमार रावत के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम शाही जामा मस्जिद के संरक्षण कार्य और संरचनात्मक मजबूती की जांच के लिए परिसर में पहुंची थी। टीम ने मस्जिद के अन्य हिस्सों का निरीक्षण प्रारंभ किया, लेकिन जब वे मुख्य स्मारक क्षेत्र—यानि मस्जिद के प्रमुख गुंबद—की ओर बढ़े, तो कमेटी के दो सदस्य हाफिज और मोहम्मद काशिफ खान ने उन्हें रोक दिया। टीम की ओर से बताया गया कि निरीक्षण प्रक्रिया पूरी तरह नियमित थी और पूर्व सूचना भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान एक अन्य व्यक्ति द्वारा भी विवाद बढ़ाने और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने की बात सामने आई है।

परिस्थिति बिगड़ती देख एएसआई टीम ने बिना निरीक्षण पूरा किए वहां से लौटने का निर्णय लिया। मेरठ वापस पहुंचते ही अधिकारियों ने पूरी घटना की जानकारी अपने विभाग को लिखित रूप में भेजी। एएसआई मेरठ मंडल द्वारा भेजे गए इसी पत्र को आधार बनाते हुए संभल पुलिस ने 14 नवंबर को शिकायत दर्ज की और दोनों कमेटी सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 132, 352 और 351(2) में एफआईआर दर्ज की। इन धाराओं में सरकारी कार्य में बाधा डालना, सरकारी कर्मचारी से दुर्व्यवहार करना और धमकी या आक्रामक व्यवहार जैसी गंभीर प्रवृत्तियों को शामिल किया गया है।

पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि शिकायत मिलते ही टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। साथ ही मस्जिद परिसर के प्रबंधन और एएसआई के बीच भविष्य में निरीक्षण को लेकर उचित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। स्थानीय लोगों के बीच भी इस घटना को लेकर चर्चा है, क्योंकि शाही जामा मस्जिद क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर स्थल है और इसके संरक्षण में किसी भी तरह की बाधा प्रशासन को चिंतित करती है। यह पूरा मामला अब उन स्थितियों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, जिनमें धरोहरों की सुरक्षा और धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के बीच समन्वय की कमी विवाद का रूप ले लेती है। एएसआई जल्द ही मस्जिद का निरीक्षण फिर से करने की तैयारी कर रहा है, ताकि संरचना से संबंधित जरूरी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर संरक्षण कार्य आगे बढ़ाया जा सके। पुलिस कार्रवाई के बीच इंतजार इस बात का है कि कमेटी के दोनों सदस्य कब पुलिस की पकड़ में आते हैं और आगे यह मामला किस दिशा में बढ़ता है।

“जदयू का नया पोस्टर वायरल: ‘बिहार है खुशहाल, लौट आए नीतीश कुमार’ सीएम पद पर सियासी संकेत तेज”

(जीएनएस)। बिहार की राजनीति एक बार फिर चुनाव बाद की हलचल के बीच नए पोस्टर युद्ध में उलझ गई है। विधानसभा चुनाव–2025 के परिणाम आने के बाद जहां एनडीए गठबंधन सरकार बनाने की तैयारियों में जुटा है, वहीं जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने शनिवार को अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से ऐसा पोस्टर जारी किया है जिसने राज्य की सियासत को और गर्म कर दिया है। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर के साथ लिखा है— “बिहार है खुशहाल, फिर से आ गए नीतीश कुमार।” पोस्टर के नीचे कैप्शन भी उसी भाषा में दिया गया— “खुशहाल है बिहार सुरक्षित है बिहार।” यह संदेश चुनाव के तुरंत बाद ऐसे समय में सामने आया है जब मुख्यमंत्री पद को लेकर कयासों का दौर जारी है और भाजपा तथा जदयू के समीकरणों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

नीतीश कुमार चेहरे के रूप में लंबे समय से बिहार की राजनीति में स्थिरता का प्रतीक माने जाते रहे हैं और जदयू लगातार उन्हें “सुशासन” का चेहरा बताती आई है। इस बार के चुनाव में भले ही भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो, लेकिन जदयू का यह पोस्टर साफ संकेत देता है कि पार्टी अभी भी नीतीश कुमार को ही अपने नेतृत्व का केंद्र मान रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पोस्टर एक साधारण संदेश नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है, जिसके जरिए जदयू यह बताने की कोशिश कर रही है कि गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री की भूमिका के लिए नीतीश कुमार ही सबसे उपयुक्त और अनुभवी चेहरा हैं। चुनाव परिणामों के बाद कई राजनीतिक मंचों पर यह चर्चा चल रही है कि क्या भाजपा मुख्यमंत्री पद का दावा पेश करेगी, लेकिन जदयू का यह पोस्टर उस बहस में एक नए मोड़ की तरह देखा जा रहा है।

बिहार की सियासत में पोस्टर हमेशा संकेतों की भाषा माने जाते हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब भी गठबंधन बदले या सत्ता में कोई बदलाव आया, पोस्टरों ने कई बार भविष्य के राजनीतिक फैसलों के सुराग दिए हैं। इस बार भी मामला वैसा ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि सरकार गठन अभी पूरी तरह अंतिम चरण में नहीं पहुंचा है और मुख्यमंत्री पद को लेकर एनडीए की ओर से आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई है, इसलिए जदयू के इस कदम ने नई जिज्ञासाओं को जन्म दिया है। पटना के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा अब ज़ोर पकड़ चुकी है कि जदयू इस पोस्टर के जरिए भाजपा के सामने अपनी दावेदारी को स्पष्ट कर रही है।

उधर, एनडीए के सभी घटक दल—भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोकमत पार्टी—जल्द ही औपचारिक बैठक करने वाले हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पद और मंत्रिमंडल गठन पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। भाजपा सूत्रों के अनुसार, पार्टी “सहज समाधान” चाहती है और किसी भी तरह का विवाद टालना चाहती है। लेकिन जदयू के इस पोस्टर ने तय कर दिया है कि पार्टी अपने रुख को लेकर स्पष्ट है और नीतीश कुमार के नेतृत्व को बनाए रखने पर जोर दे रही है।

राजनीतिक तापमान इसी बीच तेजी से बढ़ रहा है। सियासी विश्लेषक इसे “पोस्टर पॉलिटिक्स” का नया दौर बता रहे हैं, जहां संदेश सिर्फ जनसंपर्क का नहीं बल्कि गठबंधन के भीतर शक्ति-संतुलन का भी माध्यम बनते जा रहे हैं। अब सबकी नज़र एनडीए की होने वाली बैठक और उसके बाद आने वाले आधिकारिक ऐलान पर है, जो तय करेगा कि बिहार राज्य का अगला नेतृत्व किसके हाथ में होगा।

बायजूस में नया विवाद गहराया: निलंबित निदेशक पहुँचे NCLT, विदेशी फंडिंग पर उठाए गंभीर सवाल

(जीएनएस)। नई दिल्ली। एडटेक दिग्गज बायजूस के भीतर चल रहा संकट अब एक नए मोड़ पर पहुँच गया है। कंपनी के सह-संस्थापक और निलंबित निदेशक बायजू रवींद्रन ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी के प्रमुख कर्जदाता GLAS ट्रस्ट कंपनी ने विदेशी निवेश (FDI) की आड़ में प्रतिबंधित विदेशी कर्ज (ECB) उपलब्ध कराने की कोशिश की है, जो FEMA और दिवाला संहिता के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। रवींद्रन का कहना है कि आकाश इंस्टीट्यूट (AESL) में राइट इश्यू का लाभ उठाने के लिए TLPL को जो सौदा प्रस्तावित किया गया है, वह कानूनी रूप से FDI की श्रेणी में नहीं आता। इसे अनिवार्य रूप से विदेशी कर्ज के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनका दावा है कि कर्जदाता GLAS ट्रस्ट ने कंपनी के दिवाला समाधान के दौरान एक ऐसा वित्तीय ढाँचा पेश किया है जो RBI के दिशा-निर्देशों और FEMA के नियमों के बिल्कुल विपरीत है, और जिसे किसी भी रूप में वैध नहीं माना जा सकता।

मामले की पृष्ठभूमि में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वह आदेश है जिसमें AESL के राइट इश्यू को मंजूरी दी गई थी। AESL में TLPL की हिस्सेदारी 25.7% है और राइट इश्यू में अपने अधिकार के अनुपात में TLPL को कम से कम 25.75 करोड़ का निवेश करना होगा। परंतु TLPL पहले से ही दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में है और कंपनी की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वह यह राशि स्वयं जुटा सके। इसी वजह से प्रमुख कर्जदाता GLAS ट्रस्ट और उसकी अमेरिकी सहयोगी कंपनी ने 100 करोड़ तक के CCD खरीदने का प्रस्ताव दिया था, ताकि TLPL इस राइट इश्यू में भाग ले सके।

लेकिन विवाद यहीं उभरता है। रवींद्रन का कहना है कि CCD यानी अनिवार्य रूप से बाद में शेयर में बदलने वाले डिबेंचर को FDI दिखाया जा रहा है, जबकि उसकी संरचना ECB जैसी है, जिसे भारतीय नियमों के तहत इस तरीके से लिया ही नहीं जा सकता। उनका कहना है कि किसी भी वित्तीय साधन को मजबूरी और विकल्प—दोनों रूप में कन्वर्टिबल बताना कानूनी रूप से असंगत है और इसे RBI की नजर में बिना अनुमति विदेशी कर्ज माना जाएगा। उन्होंने NCLT से मांग की है कि 5 नवंबर की कर्जदाताओं की समिति (CoC) मीटिंग में पारित सभी सात प्रस्तावों को निरस्त किया जाए और GLAS ट्रस्ट के साथ किए गए CCD समझौते को अवैध घोषित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान इस प्रकार का इंटरिम फाइनेंस उपलब्ध कराना भी नियमों के अनुसार संभव नहीं है और यह प्रशासनिक तथा कानूनी प्रक्रियाओं को कमजोर करता है।

“दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में सनसनी: अलीगढ़ के ट्रैक पर मिला गैस सिलेंडर, लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला”

(जीएनएस)। दिल्ली में हुए हालिया विस्फोट के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में पहले से ही हाई अलर्ट जारी है, ऐसे माहौल में अलीगढ़ से रविवार तड़के एक ऐसी घटना सामने आई जिसने सुरक्षा एजेंसियों से लेकर रेलवे प्रशासन तक को हिला कर रख दिया। दिल्ली–हावड़ा मुख्य मार्ग पर कैफियत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय के अनुसार आज़मगढ़ से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी कि सुबह करीब 5:20 बजे सीमा फाटक और जेल पुल के बीच लोको पायलट की नज़र अचानक रेलवे ट्रैक पर पड़े एक एलपीजी सिलेंडर पर पड़ी। यह एक छोटा तीन किलो का घरेलू गैस सिलेंडर था, जो पटरी के ठीक बीच में रखा हुआ था। ट्रेन तेज़ गति में थी, लेकिन लोको पायलट ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर पूरे रैक को समय रहते रोक दिया, जिससे एक संभावित रेल दुर्घटना टल गई। यदि यह सिलेंडर पहियों के नीचे आता, तो न सिर्फ इंजन बल्कि कई कोच पटरी से उतर सकते थे और एक बड़ा हादसा हो सकता था।

सूचना मिलते ही पॉइंट्समैन और रेलवे स्टाफ मौके पर पहुँचे। जांच में पाया गया कि सिलेंडर पूरी तरह खाली था, लेकिन जिस तरह से उसे ट्रैक के बीच में रखा गया था, उससे रेल विभाग और पुलिस इसे सामान्य घटना मानने के लिए तैयार नहीं। स्थानीय पुलिस, आरपीएफ और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचे। आरपीएफ के सहायक आयुक्त गुलजार सिंह की टीम ने सिलेंडर को हटवाकर ट्रैक की जांच कराई और ट्रेन को आगे रवाना किया। घटनास्थल की शुरुआती जांच में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली, लेकिन प्रशासन ने इसे संदिग्ध मानते हुए गहन जांच शुरू कर दी है। रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के पेट्रोलमैन कुलदीप गुप्ता की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान अब इस बात पर है कि एक खाली सिलेंडर रेलवे ट्रैक के बीच आखिर पहुंचा कैसे। क्या यह किसी शरारती तत्व द्वारा किया गया मज़ाक था, या फिर जानबूझकर ट्रेन को पलटाने या यातायात बाधित करने की कोशिश? पुलिस इन दोनों कोणों को समान रूप से गंभीरता से देख रही है। घटना स्थल शहरी आबादी के बेहद करीब है, इसलिए संभावना यही है कि इसे कोई आसानी से रख सकता था। लेकिन दिल्ली विस्फोट के बाद मिले इनपुट्स और प्रदेश में जारी सुरक्षा अलर्ट को देखते हुए जांच एजेंसियां इसे एक संभावित साजिश की तरह भी परख रही हैं। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सीमा फाटक, आसपास की गलियों और रेलवे परिसर से निकाली जा रही है। पुलिस स्थानीय लोगों, दुकानदारों, रेल कर्मचारियों और आसपास मौजूद किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तफ्तीश कर रही है। अधिकारी सिलेंडर के स्रोत का पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि यह किस घर या दुकान से आया और कब गायब हुआ। अलीगढ़ पुलिस के अनुसार, रेलवे ट्रैक पर रखे गए इस सिलेंडर की तफ्तीश उतनी ही गंभीरता से की जा रही है जैसे किसी संभावित आतंकी साजिश की। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि “ट्रैक पर सिलेंडर मिलना सामान्य बात नहीं है। सभी कोणों से जांच की जा रही है और इसमें कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।” इस घटना के बाद रेलवे ने न सिर्फ अलीगढ़ बल्कि पूरे रूट पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस संयुक्त टीम बनाकर लगातार ट्रैक की निगरानी कर रही है। आईबी सहित केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में हैं।

इस घटना ने यात्रियों में भी चिंता पैदा कर दी है। कई यात्रियों का कहना है कि दिल्ली में हुए धमाके के बाद यह मामला उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि लोको पायलट की सतर्कता और समय पर लिए गए निर्णय के कारण एक संभावित दुर्घटना से बचा जा सका, जो ट्रेनिंग और सिस्टम की मजबूती को दर्शाता है। फिलहाल पुलिस सभी तकनीकी सबूतों—सीसीटीवी, फोरेंसिक और स्थानीय निगरानी—के आधार पर इस रहस्य तक पहुंचने की कोशिश में है कि यह सिलेंडर वहां कैसे और क्यों रखा गया था। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि यह किसी दुर्घटना की साजिश थी या शरारत, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस घटना ने पूरे तंत्र को और अधिक सतर्क कर दिया है।